सांध्य दैनिक
4PM
जिद...सच की
www.4pm.co.in www.facebook.com/4pmnewsnetwork @Editor_SanjayS YouTube @4pm NEWS NETWORK
● वर्ष: 12 ● अंक: 11 पृष्ठ: 8 ● लखनऊ, गुरुवार 12 फरवरी, 2026
मूल्य ₹ 3/-

हम ऐसी दुनिया में जीते हैं जहां फेसबुक पर हमारे बहुत से दोस्त हैं पर फिर भी हमने मानवीय लगाव खो दिया है।
-रॉबिन शर्मा

टी20 विश्वकप: भारतनामीबिया का मैच... 7 | भारत-अमेरिका व्यापार समझौते... 3 | यह भाजपा का विदाई बजट... 2

भारत बंद, मजदूर रजामंद

सदन से लेकर सड़क तक घिर गयी सरकार

» राहुल गांधी की आंधी धुंआ-धुंआ सियासत

» नए लेबर कोड्स के जरिए मजदूरों के अधिकारों पर सीधा हमला

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। मजदूरों के हितों को नजरअंदाज करने का अरोप लगाते हुए 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और किसान संगठनों ने भारत बंद का आह्वान कर सरकार के खिलाफ संघर्ष का बिगुल बजा दिया है।

ट्रेड यूनियनों के भारत बंद को राजनीतिक दलों का भी तेजी से समर्थन मिल रहा है। यानि कि सरकार सदन से लेकर सड़क तक बेहाल है। सदन में राहुल गांधी की आंधी में सरकार के सभी नैरेटिव धराशाही हो गये तो सड़क पर अब मजदूर अपने हितों की आवाज उठाने के लिए इकटठा हो रहे हैं। हालांकि कहानी में थोड़ा सा टिवस्ट भी है और कई ट्रेड यूनियनों ने खुद को हड़ताल से अलग होने की बात कही है।

राजनीतिक दलों का भारत बंद को समर्थन

दूसरी ओर, विपक्ष ने इस आंदोलन को खुला समर्थन दिया है। कांग्रेस नेताओं ने कहा है कि यह सिर्फ मजदूरों का संघर्ष नहीं बल्कि आम जनता की आवाज है। राहुल गांधी ने हाल ही में संसद में कहा था कि सरकार कारपोरेट हितों की रक्षा कर रही है मजदूरों और युवाओं की नहीं। समाजवादी पार्टी और वाम दलों ने भी भारत बंद का समर्थन किया है। उनका कहना है कि निजीकरण और श्रम सुधारों के नाम पर सामाजिक सुरक्षा कमजोर की जा रही है। वामपंथी नेता ने कहा कि जब संसद में सवालों को दबाया जाता है तो सड़क जवाब देती है।

मजदूर हितों को कमजोर किया जा रहा है!

ट्रेड यूनियनों का आरोप है कि नई श्रम संहिताओं के जरिए मजदूरों के अधिकारों को कमजोर किया जा रहा है। स्थायी रोजगार घट रहे हैं ठेका प्रणाली बढ़ रही है और निजीकरण के नाम पर सरकारी संपत्तियां बेची जा रही हैं। ट्रेड यूनियनों का कहना है कि सरकार ने उद्योगों और कारपोरेट घरानों को राहत दी लेकिन मजदूरों की आवाज को हाशिये पर डाल दिया। हालांकि कहानी में ट्विस्ट भी है। कुछ ट्रेड यूनियनों ने खुद को इस भारत बंद से अलग रखने का फैसला किया है। उनका तर्क है कि आंदोलन का तरीका अलग हो सकता है लेकिन संवाद जरूरी है। यही दशर इस आंदोलन को दिलचस्प भी बनाती है। क्या यह व्यापक जनआंदोलन बनेगा या सीमित राजनीतिक विरोध बनकर रह जाएगा?

आम आदमी पार्टी भी हड़ताल में शामिल

आम आदमी पार्टी ने 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और किसान संगठनों द्वारा गुरुवार को बुलाए गए राष्ट्रव्यापी भारत बंद का समर्थन करने का ऐलान किया है। पार्टी ने पंजाब सहित पूरे देश के मजदूरों, किसानों, दुकानदारों, छोटे व्यापारियों और आम नागरिकों से शांतिपूर्ण तरीके से भारत बंद को सफल बनाने की अपील की है। आप ने स्पष्ट किया है कि यह बंद किसी एक राजनीतिक दल का कार्यक्रम नहीं है बल्कि करोड़ों मेहनतकश लोगों के स्वाभिमान न्याय और अधिकारों की लड़ाई है। पार्टी ने कहा कि वह इस संघर्ष की अग्रिम पंक्ति में खड़ी है और पंजाब सहित देशभर में उसके कार्यकर्ता मजदूरों और किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बंद में शामिल होंगे। पार्टी ने भाजपा नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की नीतियों पर हमला बोलते हुए उन्हें मजदूर विरोधी और किसान विरोधी करार दिया। आप प्रवक्ताओं ने कहा कि केंद्र द्वारा लागू किए गए नए लेबर कोड्स के जरिए मजदूरों

के अधिकारों पर सीधा हमला किया गया है। इन नए कानूनों से नौकरी की सुरक्षा कमजोर हुई है, कानूनी संरक्षण घटा है और नियुक्ति एवं छंटनी के मामलों में नियोक्ताओं को खुली छूट दे दी गई है। इससे करोड़ों मेहनतकश लोगों के अधिकार और हित गंभीर खतरे में पड़ गए हैं।

तीखी बहस अब सड़कों पर उतरी

संसद के भीतर चल रही तीखी बहस अब सड़कों पर उतर आयी है। सदन में विपक्ष के हमलों से जूझ रही सरकार के सामने अब एक और चुनौती भारत बंद के रूप में खड़ी हो गई है। ट्रेड यूनियनों ने मजदूरों के अधिकारों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए हड़ताल का बिगुल फूंक दिया है। और इस बार मामला सिर्फ वेतन, श्रम कानून या ठेका प्रथा तक सीमित नहीं है बल्कि यह सीधा राजनीतिक टकराव बनता जा रहा है। बेरोजगारी, निजीकरण, श्रम संहिताओं और महंगाई जैसे मुद्दों पर उठे सवालों का असर अभी थमा भी नहीं था कि सड़कों पर मजदूर संगठनों ने मोर्चा खोल दिया। यह संयोग है या सियासी रणनीति यह बहस अलग है लेकिन तस्वीर साफ है कि सरकार पर दबाव बढ़ रहा है।

मजदूरों की आवाज नहीं दबाई जा सकती

भारत बंद का आह्वान करने वाली ट्रेड यूनियनों में देश के बड़े मजदूर संगठन शामिल हैं। उनका कहना है कि नई श्रम संहिताएं कर्मचारियों की सुरक्षा कम करती हैं हड़ताल के अधिकार को सीमित करती हैं और ठेका प्रथा को बढ़ावा देती हैं। यूनियन नेताओं का आरोप है कि मजदूरों की आवाज को दबाकर विकास की इमारत खड़ी नहीं की जा सकती। एक प्रमुख ट्रेड यूनियन नेता ने बयान दिया है कि हम सरकार से टकराव नहीं चाहते लेकिन अगर हमारी बात नहीं सुनी जाएगी तो सड़क ही आखिरी रास्ता है। उनका कहना है कि वेतन वृद्धि, सामाजिक सुरक्षा और स्थायी रोजगार की गारंटी जैसे मुद्दों पर सरकार क्यों चुप है?

मजदूरों-किसानों की आवाज़ नज़रअंदाज़ हुई : राहुल

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को केंद्र सरकार की नीतियों पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की नई श्रम संहिताओं और अंतरराष्ट्रीय व्यापार समझौतों के कारण देश के मजदूरों और किसानों का भविष्य अंधकार में है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल किया कि क्या वे जनता की आवाज सुनेंगे या उन पर किसी बाहरी ग्रिप (पकड़) का प्रभाव बहुत मजबूत है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने चार श्रम संहिताओं का हवाला देते हुए बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि मजदूरों और किसानों के भविष्य को नजरअंदाज किया गया है। उन्होंने सवाल किया कि क्या प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मजदूरों और किसानों की सुनेंगे या उन पर किसी ग्रिप की पकड़ बहुत मजबूत है? राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया, "आज देश भर में लाखों मजदूर और किसान अपने हक़ की आवाज बुलंद करने के लिए सड़कों पर हैं। मजदूरों को डर है कि चार श्रम संहिताएं उनके अधिकारों को कमजोर कर देंगी। उनके मुताबिक, किसानों को आशंका है कि (अमेरिका के साथ किया गया) व्यापार समझौता उनकी आजीविका पर चोट करेगा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने कहा, "मनरेगा को कमजोर या खत्म करने से गांवों का आखिरी सहारा भी छिन सकता है। जब उनके (मजदूरों और किसानों के) भविष्य से जुड़े फैसले लिए गए, तब उनकी आवाज को नजरअंदाज कर दिया गया।

राज्यों को सर्तक रहने के निर्देश

केन्द्र सरकार ने भी अपनी तैयारी कर ली है। गृह मंत्रालय ने राज्यों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। सत्ता पक्ष का कहना है कि भारत बंद राजनीति से प्रेरित है और देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। केन्द्र सरकार के मुताबिक सुधारों का विरोध विकास का विरोध है। लेकिन राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि यह टकराव सिर्फ श्रम कानूनों का नहीं है। यह उस व्यापक असंतोष का संकेत भी हो सकता है जो बेरोजगारी, महंगाई और असुरक्षा की भावना से जुड़ा है। अगर यह आंदोलन लंबा चला और जनसमर्थन बढ़ा, तो सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं।

तेजी से बदल रही है सियासत की दशा

सरकार का रुख भी सख्त है। सरकार का कहना है कि सुधारों के बिना अर्थव्यवस्था को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। सरकार का दावा है कि श्रम सुधार रोजगार सृजन के लिए जरूरी हैं और विपक्ष सिर्फ भ्रम फैला रहा है। लेकिन सवाल यह है कि अगर सब कुछ ठीक है तो सड़कों पर गुस्सा क्यों है? लोकतंत्र में जब संसद और सड़क दोनों एक साथ गरम हो जाएं तो सियासत की दिशा बदल सकती है।

यह भाजपा का विदाई बजट है : अखिलेश यादव

बोले सपा प्रमुख- आंकड़ों की बाजीगरी व प्रचार से गुमराह करने की कोशिश

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। यूपी की योगी सरकार ने भारी-भरकम बजट पेश कर दिया है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत किये गये वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट को सत्तारुढ़ भाजपा का विदाई बजट करार देते हुए आरोप लगाया कि सरकार सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी और अपने प्रचार के माध्यम से जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है।

सपा प्रमुख ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए संवाददाताओं से कहा,यह विदाई बजट है। इसके साथ ही भाजपा की विदाई भी तय है। इसके बाद अब वे लौटने वाले नहीं हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार केवल आंकड़ों से और अपने प्रचार के माध्यम से जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। यादव ने कहा, यह बजट केवल बड़े आकार का है। जनता की भलाई के लिये इसमें कुछ भी नहीं है। अगर बजट आकार में सबसे बड़ा है तो क्या हुआ ? उससे गरीब जनता, किसानों तथा नौजवानों को कितना लाभ मिल रहा है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने तो अपनी प्रेस कांफ्रेंस की शुरुआत ही पहेली बुझाकर कटाक्ष रूप से की। वहीं सपा के अन्य नेताओं ने भी बजट को निराशाजनक बताया है।

उप्र को 'एक ट्रिलियन डॉलर' की अर्थव्यवस्था बनाने को चाहिए 90 लाख करोड़ की जीएसडीपी

सपा प्रमुख ने दावा किया कि सरकार उत्तर प्रदेश को 'एक ट्रिलियन डॉलर' (एक हजार अरब डॉलर) की अर्थव्यवस्था बनाने की बात तो कर रही है लेकिन उसके अनुरूप कदम नहीं उठा रही है। उनके मुताबिक, सरकार कह रही है कि वर्ष 2024-25 में सकल राज्य घरेलू उत्पादन (जीएसडीपी) बढ़कर 30.25 लाख करोड़ रुपये हो गया और वर्ष 2025-26 में इसके 36 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने की संभावना जताई गई है। उन्होंने कहा, वास्तविकता यह है कि अगर उत्तर प्रदेश को 'एक ट्रिलियन डॉलर' की अर्थव्यवस्था बनाना है तो जीएसडीपी को 90 लाख करोड़ का होना चाहिए। सरकार बताए कि अब जब उसने अपना आखिरी बजट पेश कर दिया है तो 90 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था कहां से बनेगी? अगर हमें 'एक ट्रिलियन डॉलर' की अर्थव्यवस्था बनानी है तो विकास दर 30 प्रतिशत होनी चाहिए।

पुराने बजट का 50 प्रतिशत खर्च नहीं हो पाया

पूर्व मुख्यमंत्री ने सरकार पर पिछले बजट का एक बड़ा हिस्सा खर्च नहीं कर पाने का आरोप लगाते हुए कहा, आकार बड़ा है, मगर खर्च कितना किया। अगर हम पिछले बजट से तुलना करें तो जो औसत आ रहा है, उसके मुताबिक यह सरकार 50 प्रतिशत बजट भी खर्च नहीं कर पा रही है। उन्होंने कुछ आंकड़े पेश करते हुए कहा कि सरकार कृषि क्षेत्र में पिछले बजट में आवंटित धनराशि का सिर्फ 57 प्रतिशत हिस्सा ही खर्च कर पाई है। सपा प्रमुख ने कहा कि इसके अलावा ग्राम्य विकास में 36 प्रतिशत, पशुधन में लगभग 60 फीसदी, स्वास्थ्य में 58 प्रतिशत, महिला कल्याण में 53 फीसदी और बेसिक शिक्षा जैसे सबसे महत्वपूर्ण विभाग में सिर्फ 62 प्रतिशत बजट ही खर्च किया जा सका है।

बेरोजगारी दूर करने के लिए कोई स्पष्ट रणनीति नहीं

अखिलेश यादव ने दावा किया कि सरकार हमेशा प्रति व्यक्ति आय के आंकड़े बताकर अपनी पीठ थपथपाती है लेकिन अगर आंकड़ों के हिसाब से उत्तर प्रदेश की जो प्रति व्यक्ति आय है वह सूची में नीचे से दूसरे स्थान पर है। उन्होंने कहा, लगता है हमारे मुख्यमंत्री को उल्टी सूची दिखाई गई होगी। सरकार जिन गरीबों को राशन देने का दावा करती है उनकी प्रति व्यक्ति आय क्या है, सरकार के लोग यह बात कभी नहीं बताएंगे। सपा प्रमुख ने आरोप लगाया कि सरकार के पास बेरोजगारी दूर करने के लिए कोई स्पष्ट रणनीति नहीं है तथा जब निवेश आया नहीं और सरकार ने अपनी तरफ से बेरोजगारी दूर करने के लिए कोई बड़ा फैसला लिया नहीं तो आखिरकार इतने बड़े पैमाने पर बेरोजगारी को कैसे दूर किया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री ने सरकार पर प्रदेश के स्वास्थ्य क्षेत्र को बर्बाद करने का आरोप लगाया। साथ ही पुलिस पर भी भ्रष्टाचार के गम्भीर आरोप लगाये।

भाजपा के लोग अपना ही संकल्प पत्र भूले

उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने भाजपा के संकल्प पत्र में किए गए वादों का जिक्र करते हुए कहा कि लगता तो यह है की बजट बनाते-बनाते और फर्जी आंकड़े दिखा दिखा कर भाजपा के लोग अपना ही संकल्प पत्र भूल गए हैं। उन्होंने दावा किया, पुलिस का हाल तो यह हो गया है कि इधर हथेली गरम, उधर पुलिस नरम। जब मुकदमे ही नहीं दर्ज होंगे तो अपराध के आंकड़े अपने आप नीचे आ जाएंगे। पहले पुलिस तथा अपराधी दो टीमें होती थीं लेकिन भाजपा के महाभ्रष्टाचार की वजह से पुलिस और अपराधी एक ही टीम में आ गए हैं और भाजपा इस टीम की कप्तान है। यादव ने आरोप लगाया, संगठित अपराध में पहली बार अपराधियों के साथ सरकार और पुलिस भी शामिल है। ऐसे तमाम उदाहरण हैं जहां पर हम लोग देखते हैं कि संगठित होकर अपराध हो रहे हैं। भाजपा और पुलिस बेईमानी तथा भ्रष्टाचार के पर्यायवाची बन गए हैं।

केवल कागजी न रह जाए बजट : मायावती

» बसपा प्रमुख बोलीं - सुर्खियां बटोरने की कोशिश

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। यूपी सरकार की ओर से वर्ष 2026-27 के लिए पेश किए गए बजट पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में आज पेश किया गया 2026-27 का बजट लोक लुभावना ज्यादा तथा जनता के वास्तविक उत्थान एवं प्रदेश में सर्वसमाज व सभी क्षेत्र के विकास का कम प्रतीत होता है। फिर भी जो घोषणाएं व आश्वासन आदि जनता को देने का प्रयास किया गया है, उसका सही से समयबद्ध तरीके से अमल जरूर हो ताकि ये केवल कागजी न रह जाए।

साथ ही पिछले वर्ष के बजट का जमीनी क्रियान्वयनों का सही डाटा देकर बजट भाषण की परंपरा को वाकई में ठोस व विश्वसनीय बनाया जाता तो यह उचित होता। जबकि वर्तमान बजट भी अखबारों की सुर्खियां बटोरने वाला ज्यादा प्रतीत होता है जिससे एक बार फिर लोगों को अपने अच्छे दिन की

उम्मीदों पर पानी फिर गया लगता है। उन्होंने आगे कहा कि वैसे भी उत्तर प्रदेश के लोगों को स्थाई आमदनी वाले रोजगार व्यवस्था का इंतजार बना हुआ है, जिसको लेकर गंभीरता एवं सक्रियता की आवश्यक है। इस सम्बंध में एससी, एसटी व ओबीसी आरक्षण पर भी सरकार का समुचित ध्यान देना जरूरी है। बैकलाग की भर्ती की भी जितनी जल्दी पूर्ति हो उतना बेहतर होगा। वैसे भाजपा सरकार अगर बसपा की चारों सरकार की तरह सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय के संवैधानिक दायित्व को निष्ठा व ईमानदारी से निभाने का प्रयास करे तो यह देश व जनहित में उचित होगा। बजट भी इस दिशा में ही होना चाहिए अर्थात् बजट वर्ग व क्षेत्र विशेष का हितकारी तथा खासकर करोड़ों गरीब एवं किसान-विरोधी ना होकर उनके जीवन सुधार का माध्यम हो तो यह सही होगा।

बजट पूरी तह से झूंठे आंकड़ों और खोखले दावों से भरा हुआ: अजय राय

लखनऊ। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि प्रदेश सरकार की ओर से पेश किया गया बजट पूरी तह से झूठे आंकड़ों और खोखले दावों से भरा है। उन्होंने कहा कि हर अप्रैल माह में पिछले बजट का लगभग 30 प्रतिशत सरेंडर कर दिया जाता है। इस लिहाज से जो भी बजट पेश होता है उसमें 30 प्रतिशत कम करके आंकना चाहिए। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ मनरेगा को खत्म करने की एक सुनियोजित साजिश हो रही है जैसे पिछले बजट के मुकाबले इस वर्ष लगभग 6 करोड़ 21 लाख कम मानव दिवस सृजित किए गए। उन्होंने कहा कि 60 जनपदों के जिला चिकित्सालयों को मेडिकल कालेजों का जामा पहना दिया गया है, जिनका असली सच ये है कि उनमें अभी भी मूलभूत सुविधाएं तक मौजूद नहीं हैं।

बजट जन-अपेक्षाओं पर खरा उतरेगा : अनुपम मिश्रा

लखनऊ। राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय सचिव अनुपम मिश्रा ने कहा कि योगी सरकार का बजट जन-अपेक्षाओं पर खरा उतरेगा। श्री मिश्र ने कहा कि गरीब, किसान, श्रमिक, महिला, युवा और समाज के वंचित वर्ग के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने वाला बजट है। उन्होंने कहा पिछले नौ वर्षों में प्रदेश ने विकास, सुरक्षा और समृद्धि की दिशा में ठोस प्रगति की है। यह बजट प्रदेश को और आगे ले जाएगा।

बुजुर्गों की पेंशन में कटौती क्यों हो रही : अभय सिंह

» इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष बोले-सांसद व विधायक को सारी सुविधाएं क्यों?

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

चंडीगढ़। इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला ने विधायकों व सांसदों के पेंशन के मुद्दे को उठाते बुजुर्गों की सम्मान पेंशन काटने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि एक बार विधायक बनने पर ताउम्र पेंशन व परिवार को सुविधाएं मिलती हैं और जब वही व्यक्ति सांसद व राज्यसभा सदस्य बनता है तो उसे तीनों पेंशन मिलती हैं फिर बुजुर्गों की पेंशन क्यों काटी जा रही है।

आरोप लगाया कि चौधरी देवीलाल द्वारा शुरू की गई बुढ़ापा पेंशन पर सरकार ने शर्तें लगाकर एक लाख से अधिक बुजुर्गों की पेंशन बंद कर दी जबकि 1 नवंबर से 3200 रुपये पेंशन देने का वादा किया गया था। उन्होंने कहा कि बजट सत्र में विधायक यह मुद्दा उठाएंगे। 20 फरवरी को पंचकूला में हजारों प्रभावित बुजुर्गों के साथ प्रदर्शन कर राज्यपाल को ज्ञापन दिया जाएगा। चौटाला ने कहा कि अगर पेंशन नहीं काटी गई तो गांव-गांव सर्टिफिकेट जमा कराने का प्रचार क्यों हो रहा है। उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि पहले पेंशन पर शर्तें उसी ने लगाई थीं। उन्होंने बताया कि 1987 में देवीलाल ने 65 वर्ष आयु पर पेंशन शुरू की थी, जबकि 1992 में शर्तें लगाई गईं।

टीएमसी और वित्तमंत्री में तीखी नोकझोंक

निर्मल सीतारमण बोलीं- बंगाल में बम चलता है, कानून नहीं, अभिषेक बनर्जी के आरोपों का दिया जवाब

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस सरकार पर करारा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि बंगाल में बम चलता है, कानून नहीं। सदन में विपक्षी सदस्यों के शोर-गुल के बीच, उन्होंने राज्य में महिलाओं के साथ हुई कुछ हालिया घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि ममता बनर्जी सरकार कानून-व्यवस्था को बेहतर करने के बजाय दोष महिलाओं पर मढ़ रही है।

तथ्यों को तोड़मरोड़ कर किया गया पेश : अभिषेक बनर्जी

बंगाल में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। वित्त मंत्री ने बजट पर चर्चा के दौरान तृणमूल कांग्रेस सदस्य अभिषेक बनर्जी की ओर से जीएसटी को लेकर गलत दावा करने का भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि मैंने अभिषेक बनर्जी का भाषण ध्यान से सुना, मगर मुझे दुख हो रहा कि तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर इस सदन में एकदम गलत बयान दिया गया।

वित्त मंत्री केंद्रीय बजट पर सदन में हुई चर्चा का जवाब दे रही थीं। उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि माननीय मुख्यमंत्री एक महिला होते हुए भी बोल रही हैं कि अगर महिला, विशेष रूप से लड़की हो तो रात्रि के समय बाहर नहीं जाओ। आप कानून-व्यवस्था को बेहतर नहीं कर रहे हैं, मगर महिला के उपर दोष डालते जा रहे हैं। उन्होंने राज्य के दुर्गापुर में एक एमबीबीएस छात्रा के साथ अक्टूबर 2025 में हुए सामूहिक दुष्कर्म की घटना का जिक्र करते हुए यह बात कही। निर्मला सीतारमण ने आश्चर्य जताते हुए कहा कि हमारे एक सांसद का कहना है कि अगर कोई मित्र दुष्कर्म करता है तो दूसरा व्यक्ति इस पर क्या कर सकता है? उन्होंने नदिया जिले के कालीगंज में जून 2025 में हुए उपचुनाव में तृणमूल कांग्रेस की जीत के बाद विजय रैली में विस्फोट में एक बच्ची की जान चली जाने की घटना के संदर्भ में कहा कि इस मामले में तृणमूल कांग्रेस का एक नेता गिरफ्तार हुआ था।

भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर रार

डील पर विपक्ष भाजपा को नहीं देगा ढील

» विपक्ष के निशाने पर एनडीए सरकार

» कांग्रेस व सपा ने कहा आत्मघाती कदम

» खरगे, राहुल व अखिलेश ने मोर्चा संभाला

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर रार खतम नहीं हो रही है। विपक्ष इस मामले में एनडीए सरकार पर कोई ढील नहीं देना चाहता है तो सरकार हर मंच से बस यही कह रही है कि देश हित में कोई समझौता नहीं किया गया है। सपा व कांग्रेस जहां मोदी सरकार पर हलमावर है। वहीं बजट को लेकर भी सरकार को घेरा गया है। उधर बजट सत्र के दौरान नेता प्रतिपक्ष ने भी भाजपा पर प्रहार किए हैं।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर सवाल उठाते हुए दावा किया कि व्हाइट हाउस के तथ्य-पत्र में रूसी तेल खरीद रोकने जैसी शर्तें हैं, जो भारत की संप्रभुता को कमजोर करती हैं और यह समझौता किसानों और कपड़ा उद्योग के हितों की अनदेखी करता है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने भारत-अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते के ढांचे को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए दावा किया कि यह भारत की रणनीतिक स्वायत्तता, किसानों, पशुधन और कपड़ा क्षेत्र को कमजोर करता है। इस समझौते को जनसंपर्क का दिखावा बताते हुए खरगे ने सवाल उठाया कि क्या यह भारत के रणनीतिक और आर्थिक हितों की रक्षा करता है। खरगे ने कहा कि 9 फरवरी को जारी व्हाइट हाउस के समझौते संबंधी तथ्य पत्र में ऐसी शर्तें बताई गई हैं जो 6 फरवरी के भारत-अमेरिका संयुक्त वक्तव्य में शामिल नहीं थीं। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्रीय बजट को दिशाहीन बताते हुए भाजपा सरकार पर तीखा हमला किया और अमेरिका के साथ हुए व्यापार समझौते को डील की बजाय ढील करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि विदेशी आयात पर निर्भरता बढ़ाकर और अमेरिकी उत्पादों पर शून्य शुल्क लगाकर सरकार भारतीय किसानों को बर्बाद कर रही है।

महत्वपूर्ण व्यापार समझौते की वाह-वाही की होड़

सरकार की मंत्रियों की ओर से इसमहत्वपूर्ण व्यापार समझौते की वाह-वाही की होड़ लगी है। हम आपको बता दें कि यह टिप्पणी ऐसे समय आई जब भारत और अमेरिका ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण व्यापार समझौते की घोषणा की है। शनिवार को जारी संयुक्त बयान में दोनों देशों ने समझौते के मुख्य बिंदुओं को साझा किया। इस समझौते के तहत अमेरिका में प्रवेश करने वाले कई भारतीय उत्पादों पर शुल्क 50 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया जाएगा। यह फैसला फरवरी 2025 से शुरू हुई लंबी वार्ताओं के बाद संभव हुआ है। देखा जाये तो भारत के लिए यह समझौता कई क्षेत्रों में राहत लेकर आया है। जिन उत्पादों को लाभ मिलेगा उनमें वस्त्र और परिधान, चमड़ा और जूते-चप्पल, प्लास्टिक एवं रबर उत्पाद, ऑर्गेनिक केमिकल्स, होम डेकोर आइटम, हस्तशिल्प और कुछ मशीनरी उत्पाद शामिल हैं। इन क्षेत्रों में शुल्क घटने से भारतीय निर्यातकों की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी और अमेरिकी बाजार में उनकी पहुंच आसान होगी। दूसरी ओर, भारत ने भी अमेरिकी उत्पादों पर शुल्क कम करने या समाप्त करने पर सहमति दी है। इसमें अमेरिकी औद्योगिक उत्पादों की पूरी श्रृंखला के साथ-साथ कृषि और खाद्य उत्पादों का बड़ा दायरा शामिल है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह समझौता दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को नई मजबूती देगा। एक ओर जहां भारतीय निर्यातकों को बड़ा बाजार मिलेगा, वहीं अमेरिकी उत्पादकों के लिए भारत जैसे विशाल उपभोक्ता बाजार में अवसर बढ़ेंगे। साथ ही यह समझौता रणनीतिक साझेदारी को भी गहरा करेगा, क्योंकि व्यापार अक्सर व्यापक कूटनीतिक रिश्तों का आधार बनता है।

ट्रम्प ने सार्वजनिक रूप से भारत को घेरा : खरगे

खरगे ने इस बात पर जोर दिया कि वक्तव्य में रूस से तेल खरीदना बंद करने की भारत की प्रतिबद्धता को 25 प्रतिशत अतिरिक्त अमेरिकी शुल्क हटाने की शर्त के रूप में सूचीबद्ध किया गया था, जो उनके अनुसार भारत की संप्रभुता का हनन है। एक पोस्ट में, खरगे ने लिखा कि हमें बताया गया था कि भारत-अमेरिका संयुक्त वक्तव्य में रूसी तेल के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, जबकि श्री ट्रम्प ने सार्वजनिक रूप से इसके विपरीत ट्वीट किया था। अब व्हाइट हाउस के फैक्ट शीट में स्पष्ट रूप से रूसी संघ से तेल खरीदना बंद करने की भारत की प्रतिबद्धता को अतिरिक्त 25 प्रतिशत टैरिफ हटाने की शर्त के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। मोदी सरकार ने भारत की संप्रभुता के इस हनन पर सहमति जताई। क्यों? कांग्रेस पार्टी ने पहले ही उस कार्यकारी आदेश का खुलासा कर दिया था जिसके तहत भारत को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तेल आयात के लिए अमेरिकी निगरानी में रखा गया था।

कृषि को लेकर भी चिंता बढ़ी

खरगे ने कृषि को लेकर भी चिंता जताई और आरोप लगाया कि दालें और आनुवंशिक रूप से संशोधित (जीएम) चारा, जिसमें सूखे डिस्टिलर्स ग्रेन्स (डीडीजी) और पशुओं के चारे के लिए लाल ज्वार शामिल हैं, को चुपचाप समझौते में शामिल कर लिया गया है। उन्होंने चेतावनी दी कि इसके परिणामस्वरूप 2 करोड़ दुधारू किसान और देश की पशुधन आबादी प्रभावित हो सकती है। पोस्ट में लिखा था कि भारत के इतिहास में पहली बार किसी सरकार ने हमारी कृषि को विदेशी वस्तुओं के लिए पूरी तरह खोल दिया है। अब हमें पता चल गया है कि मोदी सरकार द्वारा स्वीकृत भारत-अमेरिका संयुक्त वक्तव्य में अतिरिक्त उत्पाद का वास्तव में क्या अर्थ था! 9 फरवरी को जारी व्हाइट हाउस के नए फैक्ट शीट में चुपचाप 'दालों' को शामिल कर लिया गया है, जो 6 फरवरी, 2026 को जारी भारत-अमेरिका संयुक्त वक्तव्य का हिस्सा नहीं था।

भारतीय कृषि को संकट में धकेलने की साजिश : अखिलेश यादव

समाजवादी पार्टी (एसपी) के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्र में भाजपा सरकार पर तीखा हमला करते हुए उस पर विदेशी आयात पर निर्भरता बढ़ाकर भारतीय कृषि को संकट में धकेलने का आरोप लगाया। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कृषि से संबंधित हर चीज विदेश से आयात की जाएगी, तो देश के किसान पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे। उन्होंने सवाल उठाया कि किसान क्या उगाएंगे, क्या बेचेंगे और अपनी मेहनत की कमाई से अपने परिवार का भरण-पोषण कैसे करेंगे। यादव ने लोकसभा में केंद्रीय बजट पर चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि बजट आने से पहले और बाद में भी अमेरिका के साथ व्यापार समझौते को लेकर बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि मैं भाजपा की सरकार से जानना चाहता हूं कि कितने देश बचे हैं जिनसे मुक्त व्यापार समझौता नहीं कर पाए हैं। सपा नेता ने दावा किया कि अमेरिका के साथ डील नहीं, ढील हुई है। अगर यही डील होनी थी तो 11 महीने इंतजार क्यों करवाया गया।

वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का मजाक वायरल

केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने मजाक मजाक में अमेरिका को सीधे सीधे वो संदेश दे दिया है जोकि हर भारतीय देना चाह रहा था। हम आपको बता दें कि केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने व्यापार और खेल के बीच समानता बताते हुए भारत-अमेरिका संबंधों पर हल्के-फुल्के अंदाज में टिप्पणी की है जोकि सोशल मीडिया पर छा गई है। भारत में अमेरिकी राजदूत के आवास पर सोमवार को एक स्वागत समारोह आयोजित किया गया था, जहां हाल में संपन्न भारत-अमेरिका टी20 विश्व कप मुकाबले और दोनों देशों के बीच हुए व्यापार समझौते का संदर्भ एक साथ जुड़ गया। कार्यक्रम में बोलते हुए पीयूष गोयल ने कहा कि अमेरिका द्वारा भारतीय वस्तुओं पर लगाया गया 18 प्रतिशत शुल्क उन्हें उस अंतर की याद दिलाता है जिससे भारत ने टी20 विश्व कप मैच में अमेरिका को हराया। उन्होंने इस तुलना को पूरी तरह दोस्ताना और सकारात्मक भावना से जोड़ते हुए कहा कि खेल और व्यापार दोनों में प्रतिस्पर्धा के साथ सहयोग की भी बड़ी भूमिका होती है। पीयूष गोयल ने अमेरिकी क्रिकेट टीम के प्रदर्शन की खुलकर सराहना की। उन्होंने कहा कि जिस देश

में क्रिकेट पारंपरिक रूप से लोकप्रिय खेल नहीं रहा और जिसने कुछ ही वर्षों पहले इस खेल को गंभीरता से अपनाया है, उसके लिए ऐसा प्रदर्शन शानदार कहा जाएगा। उन्होंने कहा कि अमेरिकी टीम ने जिस स्तर का खेल दिखाया, वह क्रिकेट के वैश्वीकरण का संकेत है और यह बताता है कि खेल अब नए बाजारों और समाजों में भी जगह बना रहा है। वाणिज्य मंत्री ने मैच के दौरान अमेरिकी राजदूत के साथ हुई एक हल्की-फुल्की बातचीत का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि मैच देखते समय राजदूत ने इस ओर ध्यान दिलाया कि अमेरिका 18 प्रतिशत के अंतर से मैच हारा। इस पर पीयूष गोयल ने मुस्कराते हुए सुझाव दिया कि यदि रेसिप्रोकल टैरिफ यानी पारस्परिक शुल्क शून्य कर दिया जाता, तो शायद मैच का नतीजा भी अलग होता। इस टिप्पणी पर कार्यक्रम में मौजूद लोगों के बीच हंसी का माहौल बन गया, लेकिन इसके पीछे व्यापारिक संदेश भी छिपा था कि दोनों देश टैरिफ कम कर आपसी व्यापार बढ़ा सकते हैं। बहरहाल, पीयूष गोयल की खेल-प्रेरित टिप्पणी ने यह भी दिखाया कि कूटनीति हमेशा औपचारिक और कठोर भाषा में ही नहीं होती; कभी-कभी हल्का हास्य भी बड़े संदेश दे जाता है। क्रिकेट के मैदान से निकली यह 18 प्रतिशत की तुलना अब भारत-अमेरिका व्यापारिक रिश्तों की चर्चा में एक यादगार संदर्भ बन चुकी है।

भाजपा का गणित में शून्य और 18 बराबर

उन्होंने भारतीय उत्पादों पर अमेरिका के 18 प्रतिशत शुल्क और अमेरिकी उत्पादों पर भारत में शून्य शुल्क का हवाला देते हुए कटाक्ष किया कि हमारे देश की जनता जानना चाहती है कि शून्य बड़ा है या 18? क्या भाजपा का गणित यह है कि शून्य और 18 बराबर हैं? उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि जब सब कुछ विदेश से आएगा तो देश के किसान क्या उगाएंगे? उन्होंने आरोप लगाया कि यह बजट दिशाहीन है और इसे लेकर कोई दृष्टिकोण नहीं है कि 2047 तक भारत कैसे विकसित बनेगा। यादव का कहना था कि इस बजट में 'पीडीए' (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) के लिए कुछ नहीं है। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि किसान और मजदूर बजट में अपने लिए मिली राहत को दूरबीन से देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने दावा किया कि "प्रधान संसदीय क्षेत्र" वाराणसी में राजमाता अहिल्याबाई होल्कर की मूर्ति को बुलडोजर से तोड़ दिया गया। यादव ने दावा किया कि वाराणसी में वहां लगभग 100 मंदिरों को तोड़ दिया गया है। नेपाल नरेश की ओर भेंट किया गया घंटा भी लापता है।

जिद... सच की

Sanjay Sharma

editor.sanjayasharma

@Editor_Sanjay

आखिर कब पटेंगे लापरवाही के गड्ढे

> क्या विकास का अर्थ यह हो गया है कि सड़कों पर चलते हुए हर नागरिक अपनी जान हथेली पर रखे। क्या शहरों की चमक-दमक और बड़े-बड़े दावों के बीच आम आदमी का जीवन इतना सस्ता हो गया है कि उसकी मौत पर सिर्फ एक खबर छप जाए, दो दिन बहस हो और फिर सब कुछ सामान्य हो जाए।

राजधानी दिल्ली में एक हफ्ते के अंदर गड्ढे में गिरने की वजह से दो लोग अपनी जान गवां बैठे। एकबार फिर व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए। एक घटना को घटित हुए अभी कुछ ही दिन हुए पर सरकारी काम का तरीका नहीं बदला और एक और मौत हो गई। ऐसा नहीं की यह हाल केवल दिल्ली में हो इस तरह की घटनाएं पूरे देश में हो रही हैं। जांच के बाद सबमें एक कारण समान है लापरवाही। गड्ढों में गिरी व्यवस्था में समाप्त होता जीवन आज के भारत की एक ऐसी विडंबना बन चुका है, जिसे देखकर मन भीतर तक सिहर उठता है। नोएडा में कार सवार युवा इंजीनियर की गड्ढे में गिरकर मौत का दर्द अभी समाज के मन से उतरा भी नहीं था कि दिल्ली में बाइक सवार युवक व मजदूर की जान एक खुले गड्ढे ने लील ली। दोनों घटनाओं में समानता यह है कि गड्ढे प्रशासन द्वारा विकास या मरम्मत के नाम पर खोदे गए थे और दोनों जगह न तो कोई बैरिकेडिंग थी, न चेतावनी बोर्ड, न रोशनी की व्यवस्था।

मानो व्यवस्था ने पहले गड्ढा खोदा और फिर निश्चिंत होकर वहां से हट गई कि अब जो होगा, वह नागरिक की किस्मत है। यही वह सोच है जो किसी भी समाज को भीतर से खोखला कर देती है। प्रश्न यह नहीं है कि गड्ढे क्यों खोदे गए, प्रश्न यह है कि गड्ढे खोदकर लोगों को मौत के मुंह में धकेलने का अधिकार प्रशासन को किसने दिया। क्या विकास का अर्थ यह हो गया है कि सड़कों पर चलते हुए हर नागरिक अपनी जान हथेली पर रखे। क्या शहरों की चमक-दमक और बड़े-बड़े दावों के बीच आम आदमी का जीवन इतना सस्ता हो गया है कि उसकी मौत पर सिर्फ एक खबर छप जाए, दो दिन बहस हो और फिर सब कुछ सामान्य हो जाए। यह सामान्य हो जाना ही सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि जब मौतें सामान्य लगने लगें, तब व्यवस्था की संवेदनशीलता मर चुकी होती है। दिल्ली जल बोर्ड द्वारा खोदा गया गड्ढा हो या नोएडा की किसी एजेंसी का, जिम्मेदारी तय करने की प्रक्रिया हर बार एक जैसी रहती है। अफसर निलंबित कर दिए जाते हैं, जांच समितियां बना दी जाती हैं, 24 या 48 घंटे में रिपोर्ट देने की घोषणा होती है और कुछ समय बाद वही फाइलें धूल फांकने लगती हैं। निलंबन और जांच अब समाधान नहीं, बल्कि एक औपचारिक रस्म बन गई है। सवाल यह है कि क्या निलंबन से मरे हुए बेटे लौट आते हैं, क्या जांच समितियों से टूटे हुए परिवार फिर से जुड़ जाते हैं। जब तक जवाबदेही केवल कागजों पर सिमटी रहेगी, तब तक गड्ढों में गिरती जिंदगियां यूं ही व्यवस्था का शिकार बनती रहेंगी।

(इस लेख पर आप अपनी राय 9559286005 पर एसएमएस या info@4pm.co.in पर ई-मेल भी कर सकते हैं)

किशोरों की यौन स्वायत्तता से जुड़े यक्ष प्रश्न

केपी सिंह

किशोर यौन शोषण संरक्षण अधिनियम, 2012 (पोक्सो एक्ट) के दुरुपयोग को लेकर चिन्ता व्यक्त करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने केन्द्र सरकार से यह विचार करने को कहा है कि क्यों न 'रोमियो-जूलियट' उपबन्ध जोड़कर किशोरों के बीच पारस्परिक सहमति से बने यौन व्यवहार को अपराध के दायरे से बाहर कर दिया जाए। इस परामर्श का उद्देश्य किशोरों को अपराधीकरण से बचाने के साथ उनकी यौन स्वायत्तता को व्यावहारिकता के नजरिए से देखना भी है। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के प्रकाशन 'क्राइम इन इण्डिया-2023' के अनुसार पूरे देश में 'पोक्सो एक्ट' के अन्तर्गत कुल 7,305 मामले दर्ज हुए थे, इनमें से 4,321 मामले बलात्कार, 2,619 गलत यौन-स्पर्श और 264 मामले अन्य प्रकार के यौन-उत्पीड़न से सम्बन्धित थे।

इन मामलों में 18 वर्ष से कम आयु के 2,478 नाबालिगों की संलिप्तता भी पाई गई थी जिन्हें हिरासत में लिया गया था। 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों के बीच शारीरिक सम्बन्ध 'पोक्सो एक्ट' के प्रावधानों के अनुसार पूर्णतया प्रतिबन्धित है और घोषित संगीन अपराध है। अत: नाबालिगों के बीच सहमति से बने शारीरिक सम्बन्धों के मामलों में कानून लागू करने वाली एजेंसियां अक्सर इस दुविधा में पड़ जाती है कि कानून को 'जैसा है वैसा ही' लागू किया जाए या 'जैसा होना चाहिए' वैसा लागू किया जाए। विदित हो कि कानून की व्याख्या करने और उसे 'जैसा होना चाहिए' वैसा लागू करने के आदेश देना केवल संवैधानिक न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र है। पुलिस और निचली अदालतें कानून को जस का तस लागू करने के लिए ही अधिकृत हैं, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने केन्द्र सरकार को इस विषय पर ऐसा उपाय करने का सुझाव दिया है, जिससे सहमति से यौन सम्बन्ध बनाने वाले अवयस्कों को कानून का संरक्षण प्राप्त करने के लिए बार-बार उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय की शरण में न आना-जाना पड़े। इस उपाय को सर्वोच्च न्यायालय ने 'रोमियो-जूलियट' उपबन्ध की संज्ञा दी है।

'रोमियो-जूलियट' उपबन्ध अंतर्राष्ट्रीय कानूनी प्रथाओं में पहले से ही मौजूद है, जहां अवयस्कों के बीच बने सम्बन्धों और निकटता की बारीकियों को मानव विकास प्रक्रिया का एक आवश्यक हिस्सा माना जाता है। इन कानूनों को इस प्रकार बनाया गया है कि आपराधिक यौन-विचलन और सहमति पर आधारित गैर-शोषणकारी किशोर शारीरिक सम्बन्धों

के बीच कानून लागू करने वाली संस्थाएं अपने स्तर पर ही विभेद कर सके ताकि किशोरों के अनावश्यक अपराधीकरण को रोका जा सके। संयुक्त राज्य अमेरिका के कम से कम 43 राज्यों ने यौन गतिविधियों में संलिप्त किशोरों को अपराधी बनाए जाने से बचाने के लिए 'क्लोज-इन-एज' छूट (आयु-समीपता अपवाद) सिद्धांत को अपनाया है। इस अपवाद में एक आयु वर्ग के किशोरों को अपने से नजदीक के आयु वाले अवयस्क के साथ सहमति से किया गया यौन व्यवहार को अपराध नहीं माना जाता है। कनाडा में 14 और 15 वर्ष के अवयस्क अपने से पांच वर्ष के आयु-अन्तर वाले साथी के साथ सहमति से सम्बन्ध स्थापित कर सकते हैं। फिलीपींस के कानून में 16 वर्ष की आयु वाले किशोरों को तीन वर्ष के आयु-अन्तर वाले साथी के साथ शारीरिक निकटता की अनुमति है। जॉर्जिया में नाबालिगों द्वारा परस्पर सहमति से तीन वर्ष तक के आयु-अन्तर वाले साथी के साथ यौन व्यवहार को बलात्कार नहीं दुर्व्यवहार माना जाता है। भारत में यौन सहमति की आयु 18 वर्ष है, यहां तक कि असहमति से बनाए गए सम्बन्ध को लेकर नाबालिग पत्नी अपने पति पर भी दुराचार का मुकदमा दायर कर सकती है। 'पोक्सो एक्ट' एक लिंग-निरपेक्ष कानून है और इस कानून में अवयस्कों द्वारा यौन व्यवहार के लिए दी गई पारस्परिक तथ्यात्मक सहमति की मान्यता नहीं है। तदानुसार, नाबालिगों द्वारा यौन गतिविधियों में संलिप्तता स्वत: ही अपराध बन जाती है। सहमति से सम्बन्ध स्थापित करने वाले किशोरों की सूचना पुलिस तक पहुंचाने में 'पोक्सो एक्ट' की धारा 19(1) का प्रमुख योगदान है, जिसके अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति, जिनमें चिकित्सा पेशेवर भी शामिल हैं, यदि किसी नाबालिग के यौन गतिविधि में शामिल होने की जानकारी प्राप्त कर लेता है, तो उसे इसकी सूचना पुलिस को देना कानूनी रूप से अनिवार्य हो जाती है।

परिणामस्वरूप, नाबालिग विवाहित गर्भवती महिलाएं और यौन गतिविधियों में शामिल अविवाहित किशोर अपनी चिकित्सीय समस्याओं के निदान के लिए योग्य डाक्टरों के पास जाने से कतराते हैं। झोलाछाप डाक्टरों की शरण में जाने को मजबूर होते हैं। कभी-कभी अति चिन्ताग्रस्त माता-पिता, सामाजिक दबाव के चलते अथवा व्यक्तिगत प्रतिशोध के वशीभूत, अपने बच्चों के सहमति-आधारित सम्बन्धों को बलात्कार या छेड़छाड़ के रूप में दिखा पुलिस को सूचना दे देते हैं।

आग की घटनाएं रोकने को जलस्रोतों का रखरखाव जरूरी

वीरेंद्र कुमार पैन्यूली

उत्तराखंड के पहाड़ों में पिछले साल दिसम्बर माह में गढ़वाल मंडल में टिहरी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग व चमोली के जंगलों में आग लगने की खबरें आने लगी थीं। उस समय जोशीमठ, बदरीनाथ व केदारनाथ के वन क्षेत्रों में भी आग लगी थी। केदारनाथ सेंक्चुरी व बागेश्वर के ग्लेशियर्स वन क्षेत्र भी प्रभावित हुए थे। जनवरी, 2026 के आखिरी सप्ताह तक जब तक हल्की बारिश और हिमपात नहीं हुआ था, छिटपुट वनाग्नियां लगती रहीं। अब फिर इस माह यानी फरवरी में खासकर कुमाऊं में चीड़ बहुल क्षेत्रों में आग लगने की खबरें आ रही हैं। ऐसे में जब देश में फायर सीजन निचले इलाकों में फरवरी के बाद ही माना जाता है तो मौसम बदलाव के दौर में जाड़ों के माह की दावाग्नियों को गंभीरता से लेना चाहिए। ठंड के दिनों में जंगल की आग की घटना में ग्रामीण रात-रात भर जागकर आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं।

हिमालयी दुर्गम क्षेत्रों में जाड़ों में पहुंचना ज्यादा मुश्किल हो जाता है। जनवरी, 2016 में कई जगहों पर जंगलों में आग लगी थी। इस तरह से जंगलों में जाड़ों में लगने वाली आगों से निपटने की कोई तैयारी नही थीं। हालांकि, उस समय कई सौ करोड़ रुपयों की राज्य जलवायु बदलाव कार्य योजना लागू थी। वर्ष 2017 में ही उत्तराखंड वन विभाग के शीर्ष अधिकारियों का कहना था कि सभी वन प्रभाग अपनी-अपनी कार्ययोजनायें उत्तराखंड स्टेट क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान के व्यवहारों व पद्धतियों के अनुरूप बनायेंगे। ऐसा हुआ होता तो जाड़ों की वनाग्नियां लगातार बढ़ती न रहतीं। सवाल है कि 2014 के बाद जो स्टेट क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान राज्य में जारी है, और जिसकी नोडल एजेंसी वन विभाग ही है, वह वनाग्नि कम करने में नाकारा क्यों है? मध्य भारत व पूर्वोत्तर के राज्यों में देश की करीब तीन-चौथाई जंगलों में आग लगने की घटनायें होती हैं। जब मध्य फरवरी से ही सामान्य फायर सीजन शुरू हो जाता है, तो जनवरी में वैसे भी फायर लाइन खींचने, नीचे गिरे झाड़-झंखाड़ और पत्तियों को जमा करने के लिए वन कर्मी मौजूद रहते हैं।

ऐसे में मानवीय असावधानियों या जानबूझकर आग लगाने पर रोक तब भी लगाई जा सकती है। वर्ष 2016 में उत्तराखंड में व्यापक पैमाने पर जंगलों में आग लगी थी। उस समय नैनीताल हाईकोर्ट के निर्देशानुसार वनाग्नि आपदाओं के प्रबंधन के लिए गांव स्तर पर भी कमेटियां गठित करनी थीं। लेकिन एक याचिका के जरिये हाईकोर्ट के संज्ञान में लाया गया कि 2021 अप्रैल तक भी ग्रामस्तरीय कमेटियां गठित नहीं हुईं। दरअसल देश में उत्तराखंड की पहचान उन राज्यों में होती है, जहां वनाधिकार कानून लागू करने में उदासीनता रही है। मोटर मार्ग भी जलते जंगलों की चपेट में आ जाते हैं। स्कूल जाने के एक-तिहाई रास्ते आग संभावित जंगलों से गुजरते हैं। वहीं स्मॉग से आंख, नाक व फेफड़ों के रोग भी बढ़ जाते हैं। जंगलों की आग का प्रबंधन और रोकथाम राज्यों का विषय है। हर राज्य की दावानलों के प्रबंधन की अपनी कार्ययोजना होती है। वर्ष 2000 में राज्य बनने के बाद उत्तराखंड की लगभग पचास हजार हेक्टेयर भूमि वनाग्नियों की भेंट चढ़ चुकी है।

राज्य का 38000 वर्ग किलोमीटर यानी 71 प्रतिशत क्षेत्र जंगल का है। दरअसल, मौसम में बदलाव को भी वैज्ञानिक जंगलों में आग लगने का कारण मानते हैं। मार्च से तो जंगलों में आग लगना स्वाभाविक ही मान लिया जाता है। इस बार जाड़े के माह सूखे ही रहे। वैसे जंगलों की आग या तो बरसात से बुझती है या फिर ग्रामीणों के सामूहिक प्रयास से। कई बार इन प्रयासों में ग्रामीण केवल झुलसते ही नहीं हैं, बल्कि मृत्यु भी हो जाती है। वर्ष 2015 में आग बुझाने के प्रयास में दो महिलाएं मरी थीं। मई, 2009 में पौड़ी में वनों में लगी आग बुझाने की कोशिश के दौरान आठ ग्रामवासियों ने प्राणों की आहुति दी थी। असल में जहां अवैध शराब की भट्टियां हों, कटान हो रहे हों या वन तस्कर दुर्लभ जानवर मारने को आग जलाये हों, वहां आग बुझाने जाना स्थानीय जन के लिए खतरनाक हो जाता है। आग लगने के लक्षण बताते हैं कि पहाड़ों में जंगलों के जलस्रोत सूखते जा रहे हैं। कम बर्फ के चलते ऊंचाइयों पर ज्वलनशील चीड़ की पहुंच बढ़ती जा रही है। बाघ, तेंदुआ जैसे जंगली जानवर और तराई के जंगलों में हाथी भी पानी की तलाश में भी जंगलों से बाहर निकल रहे हैं। अत: इस समय बड़े पैमाने पर जंगलों में जलाशय बनाने की जरूरत है।

उन्नीसवीं शताब्दी में ही जब अंग्रेजी हुकूमत ने कुमाऊं-गढ़वाल के पर्वतीय क्षेत्रों में वनों पर सरकारी स्वामित्व स्थापित करने के प्रयास किये तो ग्रामीणों ने इसका विरोध करना प्रारंभ कर दिया। इन आंदोलनों के चलते 1930 में जनता से समझौते के तहत पंचायती वन प्रणाली लागू की गयी थी। विडंबना यह कि अंग्रेजों के समय की सशक्त वनप्रणालियां धीरे-धीरे कमजोर कर दी गई। हालांकि, आज भी वन पंचायतें हैं लेकिन वे देशी-विदेशी फंडों से संचालित व सरकारी विभागों से नियंत्रित होने लगी हैं। उत्तराखंड की वन पंचायत प्रणाली में सरकारीकरण बढ़ाकर उसे कमजोर करने से वन अधिकार अधिनियम 2006 में भी कमजोरी आयेगी। दरअसल ग्रीन बोनस में वन पंचायतों को सशक्त हितग्राही बनाया जाना चाहिए, क्योंकि पहाड़ी खेती, पशुपालन, जलापूर्ति आदि बहुत कुछ जंगलों पर ही निर्भर करते हैं। यदि आग को त्वरित रूप से नहीं बुझाया जाता है, तो गांवों के बीच पैदल मार्गों और वन विभाग के विभिन्न क्षेत्रों में नमी बनाए रखने, जलस्रोतों, तालाबों आदि के रख-रखाव के लिए और जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। वनों में यदि नमी मौजूद रहेगी तो जंगलों की आग में उग्रता नहीं आयेगी।

अदरक और दालचीनी की चाय

अदरक और दालचीनी दोनों में ही एंटी-इंफ्लेमेटरी और थर्मोजेनिक गुण होते हैं। अदरक शरीर से टॉक्सिन्स को पसीने के जरिए बाहर निकालने में मदद करता है, जबकि दालचीनी ब्लड शुगर के लेवल को नियंत्रित रखती है। इन दोनों को पानी में उबालकर हर्बल चाय के रूप में पीने से खून शुद्ध होता है और संक्रमण का खतरा कम होता है। यह ड्रिंक उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो अक्सर आलस और भारीपन महसूस करते हैं।

बॉडी डिटॉक्स के लिए पिएं ये चार ड्रिंक्स

आज की भागदौड़ भरी जिंदगी, प्रदूषण और अनहेल्दी खानपान के कारण हमारे शरीर में धीरे-धीरे विषाक्त पदार्थ जमा होने लगते हैं। ये टॉक्सिन्स न केवल हमारे पाचन तंत्र को धीमा करते हैं, बल्कि त्वचा की चमक कम करने, थकान बढ़ाने और वजन बढ़ने का कारण भी बनते हैं। ऐसे में शरीर को समय-समय पर डिटॉक्स करना बहुत जरूरी हो जाता है। बॉडी डिटॉक्स का मतलब है शरीर के अंगों, विशेषकर लिवर और किडनी से टॉक्सिन्स को बाहर निकालना ताकि वे सुचारू रूप से कार्य कर सकें। डिटॉक्सिफिकेशन के लिए कुछ नेचुरल ड्रिंक्स प्रभावी और सुरक्षित तरीका हैं। ये ड्रिंक्स मेटाबॉलिज्म को तेज करते हैं, शरीर को हाइड्रेटेड रखते हैं और अंदरूनी अंगों की अच्छे से सफाई करने में मदद करते हैं। सुबह के समय या दिन भर इन डिटॉक्स ड्रिंक्स का सेवन करने से आप न केवल एनर्जेटिक महसूस करेंगे, बल्कि इससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी काफी मजबूत होगी।

खीरा और पुदीना

खीरा शरीर को ठंडक पहुंचाता है और इसमें पानी की मात्रा बहुत अधिक होती है, जो किडनी को साफ करने में मदद करती है। पुदीना पाचन को शांत करता है और स्वाद को ताजा बनाता है। एक जग पानी में खीरे के स्लाइस और पुदीने की पत्तियां डालकर रात भर छोड़ दें और अगले दिन इस पानी का सेवन करें। यह ड्रिंक न केवल शरीर को हाइड्रेट करता है बल्कि पेट की चर्बी घटाने में भी काफी मददगार होता है।

ग्रीन टी

ग्रीन टी केवल वजन घटाने के लिए ही नहीं, बल्कि शरीर को डिटॉक्स करने के लिए भी जानी जाती है। इसमें कैटेचिन नामक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो लिवर की कार्यक्षमता को बढ़ाता है। दिन में दो बार बिना चीनी वाली ग्रीन टी पीने से शरीर के फ्री रेडिकल्स खत्म होते हैं और मेटाबॉलिज्म में सुधार होता है। यह शरीर की सूजन को कम करने और कोशिकाओं की मरम्मत करने में अत्यंत सहायक होती है।

गुनगुना पानी और नींबू का रस

बॉडी डिटॉक्स की शुरुआत करने के लिए नींबू पानी सबसे सरल और असरदार तरीका है। नींबू में विटामिन ष्ट और एंटीऑक्सीडेंट्स लिवर को सक्रिय करते हैं और शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करते हैं। रोज सुबह खाली पेट एक गिलास गुनगुने पानी में आधा नींबू मिलाकर पीने से पाचन क्रिया में सुधार होता है और शरीर का पीएच स्तर संतुलित रहता है, जिससे त्वचा में भी निखार आता है।

हंसना मना है

पत्नी- ये लो चाय के साथ कॉल्पोल खालो। पति- मुझे बुखार नहीं है। पत्नी- तो डाइजीन ले लो। पति- मुझे गैस भी नहीं है। पत्नी- तो फिर पुदीनहरा ले लो। पति- मेरा पेट भी ठीक है। पत्नी- लो कॉम्बिफ्लेम ही ले लो, हाथ-पैर दुखना बंद हो जाएगा। पति- अरे कमाल करती हो, मैं एकदम ठीक हूं, तंदुरुस्त हूं। पत्नी- तो फटाफट उठो, सफाई के साथ बहुत काम करना है।

किडनैपर - तुम्हारा बेटा अब हमारे कब्जे में है, मां- बात करवाना जरा उससे, किडनैपर ने बेटे को फोन दिया, मां- तू वहां क्या कर रहा है, अब धनिया लाके कौन देगा मुझे।

बाबा- इतना दारू पिओगे तो मरने के बाद नर्क में जाओगे। शराबी- जो दारू बेच रहा है, उसका क्या होगा? बाबा- वो भी नर्क में जाएगा। शराबी- जो शराब की दुकान के सामने नमकीन बेचता है, बाबा- उसको भी नर्क में ही जाना पड़ेगा। शराबी- फिर क्या दिक्कत है, नर्क ही ठीक है मेरे लिए।

एक सरकारी दफ्तर के बोर्ड पार लिखा था, कृपया शोर ना करे। किसी ने उसके नीचे लिख दिया, वरना हम जाग जायेंगे..

कहानी | कछुआ और खरगोश

एक वक्त की बात है, किसी घने जंगल में एक खरगोश रहता था, जिसे अपने तेज दौड़ने पर बहुत घमंड था। उसे जंगल में जो दिखता, वो उसी को अपने साथ दौड़ लगाने की चुनौती दे देता। दूसरे जानवरों के बीच वो हमेशा खुद की तारीफ करता और कई बार दूसरे का मजाक भी उड़ाता। एक बार उसे एक कछुआ दिखा, उसकी सुस्त चाल को देखते हुए खरगोश ने कछुए को भी दौड़ लगाने की चुनौती दे दी। कछुए ने खरगोश की चुनौती मान ली और दौड़ लगाने के लिए तैयार हो गया। जंगल के सभी जानवर कछुए और खरगोश की दौड़ देखने के लिए जमा हो गए। दौड़ शुरू हो गई और खरगोश तेजी से दौड़ने लगा और कछुआ अपनी धीमी चाल से आगे बढ़ने लगा। थोड़ी दूर पहुंचने के बाद खरगोश ने पीछे मुड़कर देखा, तो उसे कछुआ कहीं नहीं दिखा। खरगोश ने सोचा, कछुआ तो बहुत धीरे-धीरे चल रहा है और उसे यहां तक पहुंचने में काफी वक्त लग जाएगा, क्यों न थोड़ी देर आराम ही कर लिया जाए। यह सोचते हुए वह एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा। पेड़ के नीचे सुस्ताते-सुस्ताते कब उसकी आंख लग गई, उसे पता भी नहीं चला। उधर, कछुआ धीरे-धीरे और बिना रुके लक्ष्य तक पहुंच गया। उसकी जीत देखकर बाकी जानवरों ने तालियां बजानी शुरू कर दी। तालियों की आवाज सुनकर खरगोश की नींद खुल गई और वो दौड़कर जीत की रेखा तक पहुंचा, लेकिन कछुआ तो पहले ही जीत चुका था और खरगोश पछताता रह गया।

कहानी से सीख- इस कहानी से यही सीख मिलती है कि जो धैर्य और मेहनत से काम करता है, उसकी जीत पक्की होती है और जिन्हें खुद पर या अपने किए हुए कार्य पर घमंड होता है, उसका घमंड कभी न कभी टूटता जरूर है।

7 अंतर खोजें

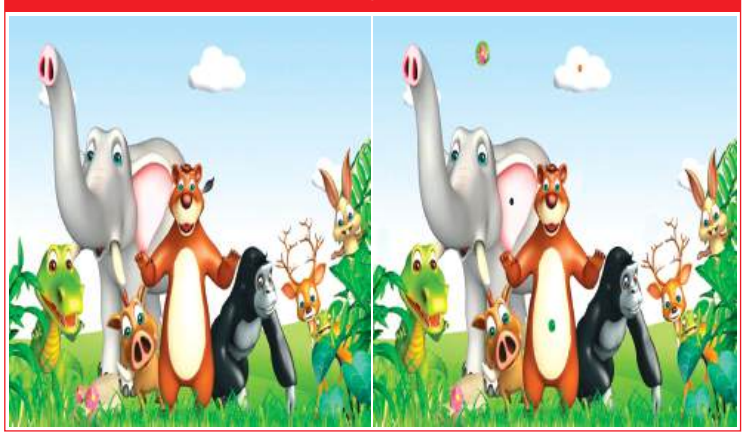

जानिए कैसा रहेगा कल का दिन

पंडित संदीप आत्रेय शास्त्री

लेखक प्रसिद्ध ज्योतिषविद हैं। सभी प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए कॉल करें-9837081951

मेष

प्रेम-प्रसंग में सफलता मिलेगी। बाहर सहायता से काम होंगे। प्रसन्नता रहेगी। संतान के संबंध में संतोष रहेगा। पुरुषार्थ का पूर्ण फल मिलेगा। थकान रहेगी।

वृषभ

संतान पक्ष की चिंता रहेगी। चोट व दुर्घटना से बचें। लेन-देन में सावधानी रखें। जोखिम व जमानत के कार्य टालें। खर्च का बोझ बढ़ेगा। किसी पर अत्यधिक भरोसा न करें।

मिथुन

सुख के साधन जुटेंगे। भूमि व भवन की योजना बनेगी। उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे। व्यवसाय ठीक चलेगा। संतान की प्रगति होगी। पारिवारिक स्थिति आनंददायक रहेगी।

कर्क

विवाद व जल्दबाजी से बचें। पार्टी व पिकनिक का आनंद मिलेगा। बौद्धिक कार्य सफल रहेंगे। प्रसन्नता रहेगी। स्वास्थ्य की ओर ध्यान दें। धन का संग्रह होगा।

सिंह

यात्रा में सावधानी रखें। विवाद को बढ़ावा न दें। दु:खद समाचार मिल सकता है। दौड़धूप अधिक होगी। वाणी पर संयम रखें। विरोधियों से सावधान रहें।

कन्या

प्रेम में सफलता मिलेगी। प्रयास सफल रहेंगे। रुके कार्यों में गति आएगी। मान-सम्मान मिलेगा। धनार्जन होगा। प्रसन्नता रहेगी। किसी से बहस न करें।

तुला

अप्रत्याशित लाभ हो सकता है। जोखिम उठाएं। यात्रा मनोरंजक रहेगी। प्रसन्नता रहेगी। धनार्जन होगा। सोच-समझकर कार्य करना लाभप्रद रहेगा।

वृश्चिक

अतिथियों का आवागमन होगा। शुभ समाचार प्राप्त होंगे। वाणी पर नियंत्रण रखें। आत्मसम्मान बना रहेगा। सामाजिक कार्यों में सक्रिय भागीदारी निभा सकेंगे।

धनु

कुसंगति से बचें। फालतू खर्च होंगे। लेन-देन में सावधानी रखें। जोखिम व जमानत के कार्य बिलकुल न करें। संतान की गतिविधियों पर नजर रखना होगी।

मकर

लेनदारी वसूल होगी। यात्रा मनोरंजक रहेगी। लाभ के अवसर मिलेंगे। व्यवसाय ठीक चलेगा। प्रसन्नता रहेगी। राज्य एवं व्यवसाय के क्षेत्र में विशेष लाभ का योग है।

कुम्भ

तीर्थयात्रा हो सकती है। सत्संग का लाभ मिलेगा। धन प्राप्ति सुगम होगी। वरिष्ठजनों का सहयोग मिलेगा। व्यापार, नौकरी में अड़चनें आने से मनोबल में कमी आ सकती है।

मीन

नई योजना बनेगी। कार्यप्रणाली में सुधार होगा। रुके कार्यों में गति आएगी। घर-बाहर प्रसन्नता रहेगी। माता के स्वास्थ्य की ओर ध्यान देना आवश्यक।

300 करोड़ के बजट से बन रही है रणवीर सिंह की अगली फिल्म प्रलय

रणवीर सिंह ने अपनी हालिया फिल्म धुरंधर से बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। यह जासूसी थ्रिलर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही और कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। अब रणवीर सिंह अपनी अगली फिल्म प्रलय को लेकर काफी उत्साहित हैं। यह एक जॉम्बी ड्रामा फिल्म है, जो उनके करियर की सबसे बड़ी और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स में से एक मानी जा रही है, जिसका बजट करोड़ों में है।

पिंकविला की एक खबर के अनुसार, इस फिल्म का बजट लगभग 300 करोड़ रुपये बताया जा रहा है। यह रणवीर सिंह की अब तक की सबसे महंगी सोलो फिल्म हो सकती है। इसमें स्क्रिप्ट से लेकर वीएफएक्स (विजुअल इफेक्ट्स) तक हर चीज में शामिल है। उन्होंने बैकएंड प्रॉफिट-शेयरिंग डील भी की है।

फिल्म का निर्देशन हंसल मेहता के बेटे जय मेहता कर रहे हैं। कहानी कोविड-19 महामारी की पृष्ठभूमि पर आधारित है, जिसमें पोस्ट-एपोकैलिप्टिक दुनिया, जॉम्बी थ्रिलर, बड़े एक्शन और परिवार की भावनात्मक कहानी होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस फिल्म में रणवीर सिंह के साथ मुख्य अभिनेत्री के रोल में कल्याणी प्रियदर्शन नजर आ सकती हैं, लेकिन अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। फिल्म की शूटिंग मई या जून 2026 में शुरू होने की उम्मीद है।

रणवीर की धुरंधर 2 जल्द ही सिनेमाघरों में आने वाली है। यह 19 मार्च को रिलीज होगी, जिसमें पहले हिस्से के कलाकार वापस आएंगे और यह और भी बड़े पैमाने पर बनी है। इसी दिन कन्नड़ एक्टर यश की फिल्म टॉक्सिक रिलीज होगी।

'लला हमसे न भिड़ियो', 69 साल की उम्र में एक्शन करते दिखे अनिल कपूर

'सूबेदार' का टीजर रिलीज

अनिल कपूर अब 69 साल की उम्र में एक्शन अवतार में वापसी कर रहे हैं। उनकी आगामी फिल्म 'सूबेदार' का टीजर आज रिलीज हुआ है। इसके साथ ही मेकर्स ने फिल्म की रिलीज डेट भी जारी कर दी है। जानिए कैसा है टीजर और कब रिलीज होगी फिल्म?

फिल्म के टीजर की शुरुआत अनिल कपूर और फैसल मलिक के सीन से होती है। टीजर में दिखाया जाता है कि अनिल कपूर के आसपास कुछ ऐसा होता है, जिससे उन्हें गुस्सा आता रहता है। लेकिन वो उस पर काबू करते रहते हैं। लेकिन अंत में उनका गुस्सा फूट जाता है और वो एक्शन मोड में नजर आते हैं। टीजर देखकर ऐसा लगता है कि कहानी बुंदेलखंडी पृष्ठभूमि पर आधारित होगी। टीजर में अनिल कपूर की आवाज में बुंदेलखंडी में डायलॉग भी सुनाई देता है। जिसमें वो कहते हैं कि 'लाला हमसे न भिड़ियो', जिसका मतलब है कि 'बेटा हमसे न टकराना।'

टीजर के साथ ही मेकर्स ने फिल्म की रिलीज डेट भी जारी कर दी है। 'सूबेदार' 5 मार्च को ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज होगी। फिल्म की कास्ट और कहानी के बारे में अभी तक ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है। फिलहाल फैंस अनिल कपूर को इस नए अवतार में देखने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। वर्कफ्रंट की बात करें तो अनिल कपूर के खाते में कई फिल्में शामिल हैं। 'सूबेदार' के अलावा उनकी आगामी फिल्मों व सीरीज में 'अल्फा', 'किंग' और 'फैमिली बिजनेस' शामिल हैं। इसके अलावा उनके 'नायक 2' बनाने की भी चर्चाएं हैं। हाल ही में अनिल कपूर अपनी बेटी सोनम कपूर के बेबी शॉवर में नजर आए थे।

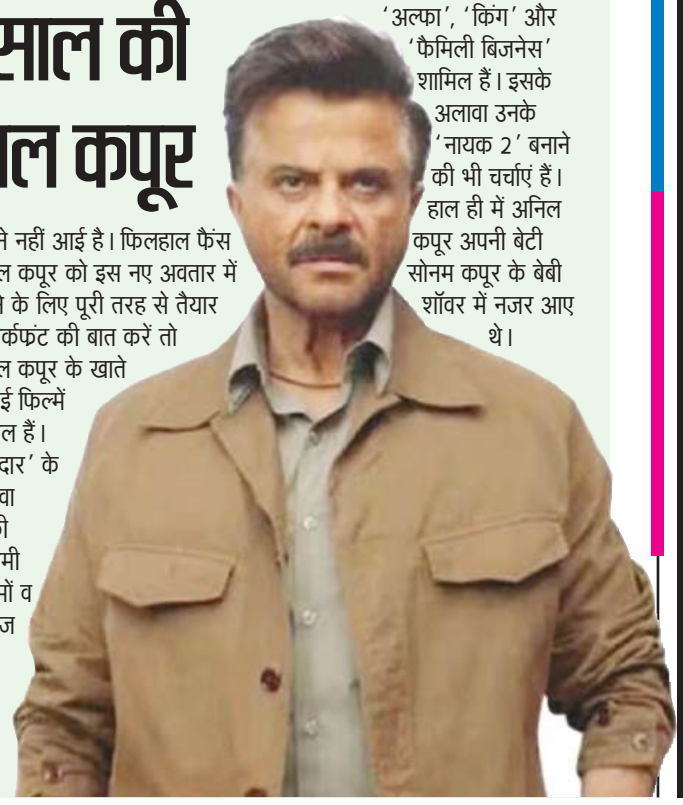

बॉलीवुड | कंट्रोवर्सी

पहली पत्नी ने उदित नारायण पर लगाया बिना अनुमति के गर्भाशय निकलवाने का आरोप

जाने माने प्लेबैक सिंगर उदित नारायण एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। उनकी पहली पत्नी रंजना ने बिहार के सुपौल स्थित महिला पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने उदित नारायण, उनके दो भाइयों और उनकी दूसरी पत्नी पर गंभीर आपराधिक आरोप लगाए हैं। रंजना ने मंगलवार को अपने वकील करुणाकांत झा के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचकर औपचारिक शिकायत दर्ज कराई। अपने आवेदन में उन्होंने आरोप लगाया है कि उनके साथ एक आपराधिक साजिश रची गई, जिसके तहत उनकी जानकारी के बिना उनका गर्भाशय निकाल दिया गया। उन्होंने दावा किया कि उन्हें इस बात का पता कई साल बाद इलाज के दौरान चला। अपनी शिकायत में रंजना ने खुद अपनी उम्र 61 साल बताई। वह सुपौल जिले के बलुआ बाजार पुलिस थाना क्षेत्र के संस्कृत निर्मली वार्ड नंबर 11 के निवासी चंद्रकांत झा की पुत्री हैं। उन्होंने बताया कि उनकी शादी उदित नारायण से 7 दिसंबर 1984 को हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार हुई थी। रंजना के अनुसार, उदित 1985 में संगीत में अपना करियर बनाने के लिए मुंबई चले आए थे। इसी दौरान,कथित तौर पर मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से उन्हें पता चला कि उदित ने दीपा नारायण नाम की एक अन्य महिला से शादी कर ली है। हालांकि, उनका दावा है कि जब भी उन्होंने इस बारे में उनसे सवाल किया, उदित उन्हें गुमराह करते रहे। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि 1996 में मेडिकल ट्रीटमेंट के बहाने से उदित अपने भाइयों संजय कुमार झा और ललित नारायण झा के साथ उन्हें दिल्ली के एक बड़े अस्पताल में ले गए। यहां उनकी सहमति और जानकारी के बिना उनका गर्भाशय निकाल दिया गया। रंजना ने दावा किया कि उस समय दीपा नारायण भी अस्पताल में मौजूद थीं।

गजब ! बिना फ्रिज, बिना केमिकल सालभर स्टोर रहेगा यह टमाटर

छत्तीसगढ़ में इन दिनों टमाटर की कीमतों में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। बाजार में टमाटर मात्र 10 रुपये किलो तक बिक रहा है। ऐसे समय में ग्रामीण अंचलों की महिलाएं टमाटर को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए पारंपरिक देसी तरीके अपनाती हैं, जिसे छत्तीसगढ़ी भाषा में 'पताल खोयला' या 'पताल फतका' कहा जाता है। यह विधि न केवल टमाटर को खराब होने से बचाती है, बल्कि महंगाई के समय घर की रसोई का सहारा भी बनती है। काफी लंबे समय से टमाटर को प्रिजर्व कर रखने वाली छत्तीसगढ़ की गृहणी सुलोचना नायक बताती हैं कि जब बाजार में टमाटर सस्ता होता है, तभी इसे खोयला बनाकर संग्रह किया जाता है। इसका महत्व तब और बढ़ जाता है, जब बाद में टमाटर की कीमतें आसमान छूने लगती हैं। उस समय यही पताल खोयला चटनी और सब्जी बनाने में उपयोग किया जाता है और बाजार पर निर्भरता कम हो जाती है। पताल खोयला बनाने की प्रक्रिया पूरी तरह प्राकृतिक और बिना किसी केमिकल प्रिजर्वेटिव के होती है। इसके लिए सबसे पहले ताजे और पके हुए टमाटरों को धोकर बड़े आकार की कढ़ाई में डाल दिया जाता है। फिर धीमी आंच पर टमाटरों को लगातार चलाते हुए पकाया जाता है। इस दौरान टमाटरों को पिचक-पिचक कर तब तक पकाया जाता है, जब तक उनका पूरा रस सूख न जाए और गाढ़ा पेस्ट जैसा रूप न बन जाए। यह प्रक्रिया लगभग 1 से 2 घंटे तक चलती है, जो टमाटर की मात्रा पर निर्भर करती है। इस दौरान चम्मच चलाते रहना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि अगर टमाटर कढ़ाई में चिपक जाए तो खोयला ठीक से तैयार नहीं हो पाता। पकने के बाद स्वाद अनुसार नमक मिलाया जाता है और फिर इस मिश्रण को 2 से 3 दिन तक धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है। पूरी तरह सूखने के बाद इसे प्लास्टिक या कांच के डिब्बों में सुरक्षित रख लिया जाता है। गृहणी सुलोचना नायक का कहना है कि यदि इन डिब्बों को फ्रिज में रखा जाए तो इसका स्वाद लगभग ताजे टमाटर जैसा बना रहता है। इसे किसी भी मौसम में उपयोग किया जा सकता है। गांवों में टमाटर खोयला का इस्तेमाल मुख्य रूप से चटनी बनाने, खट्टा सब्जी तैयार करने और दाल में खट्टापन लाने के लिए किया जाता है। आज जब महंगाई आम आदमी की रसोई पर असर डाल रही है, ऐसे में छत्तीसगढ़ की यह पारंपरिक विधि आर्थिक बचत के साथ-साथ खाद्य सुरक्षा का भी मजबूत उदाहरण बन रही है। 'पताल खोयला' न केवल स्वाद को बनाए रखता है, बल्कि ग्रामीण जीवन की समझदारी और आत्मनिर्भरता की पहचान भी है।

अजब-गजब | नारियल के अंदर पानी कहां से आता है?

पेड़ की जड़ों द्वारा जमीन से अवशोषित किया गया भूजल होता है नारियल के अंदर का पानी

दुनिया में कई ऐसी जगहें हैं जहां बेहद अनोखे और दुर्लभ फलों की पैदावार होती है। इन्हीं खास खूबियों की वजह से कुछ फल पूरी दुनिया में मशहूर हो जाते हैं। लेकिन इस मामले में भारत भी किसी से पीछे नहीं है। एक कृषि प्रधान देश होने के नाते भारत में ऐसे कई फल पाए जाते हैं जिनका स्वाद अलग होता है और जो सेहत के लिहाज से भी बेहद फायदेमंद होते हैं। इन्हीं फलों में से एक नारियल है। आज हम आपको नारियल से जुड़े कुछ हैरान करने वाले तथ्यों के बारे में बताएंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि नारियल के अंदर मौजूद पानी आखिर आता कहां से है और यह कुदरत का करिश्मा कैसे संभव होता है? अगर नहीं, तो आइए जानते हैं इसकी पूरी कहानी।

ट्रेन और हवाई यात्रा के दौरान सूखा नारियल ले जाने पर मुख्य रूप से सुरक्षा कारणों से रोक लगाई जाती है। माना जाता है कि सूखे नारियल में तेल की मात्रा काफी अधिक होती है, जिससे इसके ज्वलनशील होने का खतरा बढ़ जाता है।

वहीं, ट्रेन में इसके रेशेदार बाहरी हिस्से से आग लगने की आशंका रहती है। फ्लाइट में भी सुरक्षा नियमों के तहत सूखे नारियल को

प्रतिबंधित श्रेणी में रखा गया है। गौर करने वाली बात यह है कि नारियल मालदीव का राष्ट्रीय फल है। यह फल खासतौर पर द्वीपीय देशों की संस्कृति और अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभाता है।

नारियल मालदीव के राष्ट्रीय प्रतीक में भी शामिल है, जो वहां के लोगों के जीवन में इसके महत्व को दर्शाता है। इसके अलावा इंडोनेशिया, फिलीपींस और भारत दुनिया के सबसे बड़े नारियल उत्पादक देशों में शामिल हैं। भारत में नारियल का धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक महत्व बेहद गहरा है। यहां इसे आमतौर पर 'श्रीफल' कहा जाता है। मान्यता है कि नारियल पवित्रता, समृद्धि और शुभता का प्रतीक है, इसलिए पूजा-पाठ, विवाह और किसी भी नए कार्य की शुरुआत में इसका उपयोग किया जाता है। इसके साथ ही नारियल सेहत और आजीविका दोनों के लिए एक बेहद उपयोगी फसल मानी जाती है।

अगर आप भी यह जानना चाहते हैं कि नारियल के अंदर पानी कैसे बनता है, तो बता दें कि यह पानी दरअसल पेड़ की जड़ों द्वारा जमीन से अवशोषित किया गया भूजल होता है। यह पानी पोषक तत्वों से भरपूर होता है और जाइलम नामक संवहनी प्रणाली के जरिए तने से होते हुए फल तक पहुंचता है। इस प्रक्रिया के दौरान पेड़ खुद इस पानी को प्राकृतिक रूप से फिल्टर करता है। विकसित होते नारियल के लिए यह पानी एक जरूरी पोषक तत्व का काम करता है। नारियल पानी का मीठा स्वाद उसमें प्राकृतिक रूप से मौजूद शर्करा की वजह से होता है। यह कोई बाहरी चीनी नहीं होती, बल्कि पेड़ द्वारा मिट्टी से अवशोषित पोषक तत्वों के कारण बनती है। नारियल पानी में मिठास की मात्रा लगभग 2.5 से 5 प्रतिशत तक होती है, जो इसे न सिर्फ स्वादिष्ट बल्कि एक ताजा और पौष्टिक प्राकृतिक पेय भी बनाती है।

महाराष्ट्र के चंद्रपुर महानगरपालिका मेयर पर घमासान

शिवसेना यूबिटी और कांग्रेस में वार-पलटवार, कांग्रेस ने मांगा स्पष्टीकरण

» उद्धव गुट ने पहले भाजपा को दिया समर्थन

» कांग्रेस की गड़बड़ी के कारण स्थानीय शिवसेना-यूबीटी नेताओं ने यह निर्णय लिया : राउत

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

मुंबई। महाराष्ट्र के चंद्रपुर महानगरपालिका में वहां पर भाजपा का मेयर बन जाने के बाद सियासी संग्राम मच गया है। शिवसेना यूबिटी व कांग्रेस में वार-पलटवार जारी है। कांग्रेस नेता नाना पटोले ने कहा कि उद्धव गुट ने भाजपा का साथ दिया। उधर उद्धव गुट के नेता संजय राउत यहां ऐसी स्थिति के लिए कांग्रेस को ही जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने नसीहत देते हुए कहा कि सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद चंद्रपुर में सत्ता हासिल न कर पाने पर कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए। वहीं कांग्रेस ने भी पलटवार करते हुए एमवीए के सहयोगी पार्टी से स्पष्टीकरण मांगा है।

बता दें सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद कांग्रेस सत्ता हासिल करने से चूक गई और बीजेपी ने दांव चलते हुए अपना मेयर बना लिया। उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने दावा करते हुए कहा, उद्धव ठाकरे ने चंद्रपुर में पार्टी पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि वे बीजेपी की किसी भी तरह से मदद न करें, चाहे इसका मतलब विपक्ष में बैठना ही क्यों न हो, फिर भी कांग्रेस की गड़बड़ी के कारण स्थानीय (शिवसेना-यूबीटी) नेताओं ने यह निर्णय लिया है। इसका मतलब यह नहीं है कि हमने बीजेपी के साथ हाथ मिला लिया है। वीबीए और एआईएमआईएम ने महापौर चुनावों में कांग्रेस का समर्थन इसलिए नहीं किया क्योंकि पार्टी में एकमत नहीं था। बता दें पिछले महीने हुए 66 सदस्यीय चंद्रपुर नगर निकाय के चुनावों में कांग्रेस 27 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, जबकि बीजेपी 23 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर रही। शिवसेना (यूबीटी) ने 6 सीटें जीतीं, भारतीय शेतकरी कामगार पक्ष (जनविकास सेना) ने तीन, वंचित बहुजन अघाड़ी (वीबीए) ने 2, जबकि एआईएमआईएम, बीएसपी और शिवसेना को एक-एक सीट मिली। जबकि दो सीटें निर्दलीय उम्मीदवारों के खाते में गईं।

बीजेपी की संगीता खांडेकर बनी चंद्रपुर की मेयर

शिवसेना (यूबीटी) और बीजेपी के बीच हुए अप्रत्याशित गठबंधन के चलते चंद्रपुर महानगरपालिका में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा. जबकि यहां कांग्रेस इस पद के लिए सबसे ज्यादा मजबूत स्थिति में थी। बीजेपी की संगीता खांडेकर ने कांग्रेस उम्मीदवार वैशाली महादुले

को एक वोट से हराकर मेयर की कुर्सी पर कब्जा कर लिया। शिवसेना (यूबीटी) उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पार्टी यूबीटी ने यहां बीजेपी को समर्थन देकर कांग्रेस का खेल बिगाड़ दिया था। शिवसेना (यूबीटी) के पार्षद प्रशांत दानव डिप्टी मेयर चुने गए।

एमवीए की अस्तित्व पर गंभीर सवाल

इस घटनाक्र म ने विपक्षी एकता और महा विकास अघाड़ी (एमवीए) की अस्तित्व पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। महाराष्ट्र में महायुति सरकार में बीजेपी, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और एनसीपी के साथ सत्ता साझा कर रही है, वहीं शिवसेना (यूबीटी), शरद पवार की एनसीपी (एसपी) और कांग्रेस विपक्षी एमवीए के घटक हैं।

हर्षवर्धन ने मांगा जवाब

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने कहा कि शिवसेना (यूबीटी) को जवाब देना चाहिए कि उसने अपने पार्षदों को बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की खुली छूट क्यों दी? हमारे पार्षद एकजुट रहे और उन्होंने दलबदल नहीं किया. उन्होंने कहा, अगर आपको हमारी आपसी कलह से कोई आपत्ति थी, तो आप महापौर पद के लिए मतदान के दौरान अनुपस्थित रह सकते थे या वोटिंग से दूर रह सकते थे।

विकास के साथ युवाओं को चाहिए रोजगार : देवेगौड़ा

» पूर्व पीएम ने मोदी सरकार को दिखाया आइना

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। पूर्व प्रधानमंत्री और जनता दल (सेक्युलर) के प्रमुख एच डी देवेगौड़ा ने बुधवार को राज्यसभा में आम बजट 2026-27 पर चर्चा के दौरान सरकार को महत्वपूर्ण सुझाव दिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि देश की प्रगति को समावेशी बनाने के लिए नीतियों के केंद्र में रोजगार सृजन को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। जनता दल (एस) प्रमुख ने सरकार को सुझाव दिया कि अकेले विकास से काम नहीं चलेगा, नीति पर विचार करते समय रोजगार को केंद्र में रखा जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि केवल निवेश से ही संतुष्ट होकर नहीं बैठ जाना चाहिए बल्कि इस बात पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि देश के युवाओं के लिए गरिमापूर्ण रोजगार सृजित हो सकें, विशेषकर छोटे शहरों एवं ग्रामीण भारत में। उन्होंने कहा कि कराधान को सरल बनाया जाना स्वागत योग्य है किंतु कर नियमों का अनुपालन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि ईमानदार करदाताओं को सुरक्षित महसूस करना चाहिए, चिंतित नहीं। देवेगौड़ा ने कहा कि भारत वर्तमान में एक अत्यंत महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है। उन्होंने उल्लेख किया कि देश अब मध्यम आय वाले राष्ट्र से उच्च मध्यम आय वाला देश बनने के कगार पर है। उनके अनुसार, वर्तमान के सरकारी उपाय ही यह तय करेंगे कि विकास कुछ वर्गों तक सीमित रहेगा या यह वास्तव में सबका साथ सबका विकास बन पाएगा। देवेगौड़ा ने कहा कि उन्होंने भारत की विकास यात्रा के विभिन्न चेहरे देखे हैं। उन्होंने कहा कि यह बजट एक ऐसे महत्वपूर्ण समय में आया है, जब भारत एक मध्यम आय वाले राष्ट्र से उच्च मध्यम आय वाला देश बनने के कगार पर है। उन्होंने कहा, ''हमारे उपाय यह तय करेंगे कि विकास सीमित रहेगा अथवा यह वास्तव में सबका साथ सबका विकास बन पाएगा।

टी20 विश्वकप : भारत-नामीबिया का मैच आज

» मैच से पहले ईशान किशन भी चोटिल, अभिषेक के खेलने पर संशय बरकरार

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। नामीबिया के खिलाफ आज दिल्ली में भारत का मैच होना है। लेकिन उससे पहले पहले भारतीय टीम को एक और झटका लग सकता है। दरअसल, स्टार बल्लेबाज ईशान किशन अभ्यास सत्र के दौरान चोटिल हो गए। बुमराह की खतरनाक यॉर्कर से वह चोटिल हुए। इससे पहले अभिषेक शर्मा पेट में संक्रमण के कारण अस्पताल में भर्ती हुए थे। हालांकि, बुधवार को उन्हें छुट्टी मिल गई। नामीबिया के खिलाफ मैच से पहले अभ्यास सत्र के दौरान ईशान किशन शानदार लय में नजर आए, लेकिन तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की एक तेज यॉर्कर उनके बाएं पैर पर लग गई, जिससे उन्हें थोड़ी देर के लिए मैदान छोड़ना पड़ा।

हालांकि, किशन बाद में दोबारा बल्लेबाजी करने लौटे, लेकिन ज्यादा देर तक क्रीज पर नहीं टिके।

बुमराह लगातार दूसरे दिन पूरी रफ्तार से गेंदबाजी करते दिखे, जो टीम इंडिया के लिए राहत की खबर है। अब उम्मीद है कि वह नामीबिया के खिलाफ होने वाले मैच में वापसी कर सकते हैं, जो पाकिस्तान के खिलाफ कोलंबो में होने वाले मुकाबले से पहले उनके लिए अहम तैयारी साबित होगा। बुमराह ने गेंदबाजी के बाद कैचिंग ड्रिल में भी हिस्सा लिया। वहीं, अभिषेक शर्मा की तबीयत को लेकर संशय बना हुआ है। पेट में संक्रमण के कारण उन्हें दिल्ली पहुंचने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था, अगर वह समय पर फिट नहीं हो पाते हैं तो खराब फॉर्म के कारण बाहर चल रहे संजू सैमसन को मौका मिल सकता है। तिलक वर्मा ने कहा, हमारे पास अभी एक दिन और है। कल तक उनकी स्थिति साफ हो जाएगी, उसके बाद आगे का फैसला लिया जाएगा।

वेस्टइंडीज ने इंग्लैंड को 30 रन से हराया

वानखेड़े। टी20 विश्वकप के ग्रूप-सी के अहम मुकाबले में वेस्टइंडीज ने ऑलराउंड प्रदर्शन के दम पर इंग्लैंड को 30 रन से शिकस्त दी। शेरफेन रदरफोर्ड की नाबाद 76 रन की तूफानी पारी और गुडाकेश मोती की घातक स्पिन गेंदबाजी ने मैच का रुख पूरी तरह कैरेबियाई टीम के पक्ष में मोड़ दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज ने 196 रन का मजबूत स्कोर खड़ा किया, जिसके जवाब में इंग्लैंड की टीम 166 रन पर सिमट गई। इस मुकाबले में वेस्टइंडीज की शुरुआत खराब रही। टीम ने मात्र 8 रन पर शाई होप और ब्रैंडन किंग के विकेट गंवा दिए। लेकिन आखिरी 10 ओवरों में वेस्टइंडीज ने 117 रन बटोरे, जिससे टीम 196 के मजबूत स्कोर तक पहुंच सकी। 197 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की शुरुआत विस्फोटक रही। लेकिन वेस्टइंडीज के स्पिनरों ने मैच का रुख पलट दिया। गुडाकेश मोती ने 4 ओवर में 32 रन देकर 3 विकेट झटके। जिसके चलते इंग्लैंड की टीम 19 ओवर में 166 रन पर सिमट गई।

आतंक फैलाने वालों के साथ मैच क्यों खेला जा रहा है : प्रियंका चतुर्वेदी

» शिवसेना (यूबीटी) सांसद ने बीसीसीआई और सरकार पर साधा निशाना

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। शिवसेना (यूबीटी) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने टी20 विश्व कप में भारत-पाकिस्तान मैच पर बीसीसीआई की चुप्पी की आलोचना करते हुए कहा कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली क्रिकेट बोर्ड एक आतंकी देश के साथ खेलने पर पीसीबी के फैसले का इंतजार क्यों कर रहा था।

प्रियंका ने कहा कि सबसे पहले, चाहे यह पाकिस्तान का यू-टर्न हो या नहीं, मेरा सवाल सिर्फ बीसीसीआई से है। हम पीसीबी और आईसीसी की ओर क्यों देख रहे थे कि मैच होना चाहिए या नहीं? जैसा कि उन्होंने कहा कि हम मैच नहीं खेलेंगे, क्या हमें दो बार यह नहीं कहना चाहिए था कि हम इस आतंकवादी देश के साथ मैच नहीं खेलना चाहते? इससे पहले पाकिस्तान सरकार ने अपनी राष्ट्रीय क्रिकेट टीम को विश्व कप में मौजूदा चैंपियन भारत के खिलाफ 15 फरवरी को निर्धारित मैच के लिए मैदान में उतरने का निर्देश दिया था। यह निर्णय पीसीबी के अध्यक्ष मोहसिन नकवी द्वारा प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को पीसीबी, आईसीसी और बीसीबी के बीच वार्ता के परिणामों के बारे में जानकारी देने के बाद लिया गया।

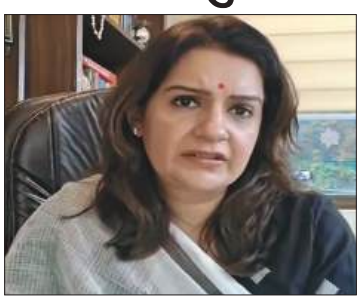

नीरस और दिशाहीन है तीसरा बजट: जूली

» नेता प्रतिपक्ष ने सरकार को घेरा

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

जयपुर। राजस्थान विधानसभा में पेश बजट पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने भजनलाल सरकार के तीसरे बजट को 'नीरस, दिशाहीन और जनता को गुमराह करने वाला' बताया। जूली ने कहा कि जिन घोषणाओं को लागू करने की बात कही जा रही है, उनके लिए बजट में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। उन्होंने सवाल उठाया कि बिना बजट प्रावधान के योजनाएं कैसे लागू होंगी। नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि बजट की लगभग 70-75 प्रतिशत घोषणाएं रूटीन प्रकृति की हैं, जिनमें सामाजिक सुरक्षा, पेयजल और अन्य पुरानी योजनाएं शामिल हैं।

जल जीवन मिशन का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि 14 लाख कनेक्शन देने का दावा किया जा रहा है, जबकि इनमें से 10 लाख से अधिक कनेक्शन कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में किए गए थे। उनके अनुसार सरकार पुरानी उपलब्धियों को अपना बताकर भ्रम फैला रही है।जूली ने कहा कि पिछली बजट घोषणाओं में से केवल 30 प्रतिशत ही पूरी हुई हैं, जबकि 30 प्रतिशत पर काम शुरू नहीं हुआ है और शेष घोषणाएं अधूरी हैं। उन्होंने रिफाइनरी परियोजना का उदाहरण देते हुए कहा कि अगस्त में इसे शुरू करने का दावा किया गया था, लेकिन फरवरी आने को है और प्रगति दिखाई नहीं दे रही है। शिक्षा क्षेत्र में जूली ने कहा कि प्रदेश में 41 हजार से अधिक स्कूल जर्जर स्थिति में हैं, जबकि बजट में केवल 2,500 स्कूलों की मरम्मत की बात की गई है। स्वास्थ्य क्षेत्र में उन्होंने कहा कि चिरंजीवी योजना का भुगतान रुका हुआ है, जिसके कारण कई अस्पताल योजना से बाहर हो गए हैं।

राज्य की आर्थिक स्थिति चिंताजनक

आर्थिक स्थिति को लेकर उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राजस्थान को कर्ज में डुबो दिया गया है। उन्होंने बताया कि एफआरबीएम सीमा 37 प्रतिशत है और कर्ज 36.8 प्रतिशत तक पहुंच चुका है। जूली ने आरोप लगाया कि पिछले तीन बजटों में जितना कर्ज लिया गया, उतना 50 वर्षों में भी नहीं लिया गया था।

संसद से लेकर सड़क तक राहुल पर भाजपा तिलमिलाई

लोस में नेता प्रतिपक्ष व जगदंबिका पाल में तीखी बहस, निशिकांत ने संसदीय सदस्यता रद्द करने की मांग की

» केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने फिर खोला कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के आक्रामक तेवर के बाद भाजपा तिलमिला गई है। भाजपा नेता निशिकांत दुबे ने की उनकी सदस्यता रद्द करने की बड़ी मांग कर दी है। उधर सदने आज भी हंगामा जारी रहा। उधर कांग्रस नेता राहुल गांधी और जगदंबिका पाल के बीच तीखी बहस हुई, जिसमें पाल ने राहुल के पूर्व कांग्रेसी तंज का जवाब देते हुए कहा कि विपक्ष के नेता को अपनी भाषा की सीमा का ध्यान रखना चाहिए और देश को गुमराह नहीं करना चाहिए।

केंद्रीय बजट पर बहस के दौरान लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कार्यवाही की अध्यक्षता कर रही जगदंबिका पाल के बीच तीखी बहस हुई। गांधी ने पाल को पूर्व कांग्रेसी सदस्य कहकर संबोधित किया, जिस पर अध्यक्ष ने प्रतिक्रि या दी। पाल ने हिंदी में जवाब दिया कि मेरी सलाह ले लिए होते, तो आज भी विपक्ष में नहीं बैठे रहते। इसी को लेकर आज पाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वह विपक्ष के नेता हैं और उन्हें अपने शब्दों और भाषा की सीमा का ध्यान रखना चाहिए। क्या इस संसदीय लोकतंत्र में ऐसा करना उचित है ?पाल ने कहा कि वह सरकार की जितनी चाहे आलोचना कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह के आरोप वह लगा रहे हैं, जिस तरीके से लगा रहे हैं, वह देश को गुमराह कर रहे है। दुनिया देश की उपलब्धियों के बारे में जानती है- कैसे भारत ने कोविड के बावजूद अपनी अर्थव्यवस्था को विश्व में 11वें स्थान से चौथे स्थान पर पहुंचाया है। बुधवार को सदन में तीखी बहस छिड़ गई जब गांधी जी ने प्रस्तावित भारत-अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते को लेकर मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला और आरोप लगाया कि इससे भारत के मूल हितों से समझौता हुआ है।

देश को गुमराह कर रहे हैं राहुल : निशिकांत दुबे

भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने गुरुवार को लोकसभा में कांग्रेस नेता और विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया है, जिसमें उन पर देश को गुमराह करने का आरोप लगाया गया है। दुबे ने राहुल गांधी की संसदीय सदस्यता रद्द करने और उन पर आजीवन चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। दुबे ने एएनआई को बताया कि मैंने आज लोकसभा में राहुल गांधी के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया है, जिसमें उन पर जॉर्ज सोरोस जैसी ताकतों की मदद से देश को गुमराह करने का आरोप लगाया गया है, जो देश को नुकसान पहुंचाना चाहती हैं। मैंने अपने प्रस्ताव में राहुल गांधी की संसदीय सदस्यता रद्द करने और उन पर आजीवन चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाने का अनुरोध किया है। यह प्रस्ताव गांधी के कल लोकसभा में दिए गए भाषण के बाद आया है, जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार पर राष्ट्रीय हितों से समझौता करने का आरोप लगाया था। लोकसभा में बोलते हुए गांधी ने कहा कि सरकार ने स्वयं स्वीकार

किया है कि विश्व एक वैश्विक संकट का सामना कर रहा है, एक महाशक्ति का युग समाप्त हो रहा है, भू-राजनीतिक संघर्ष तीव्र हो रहे हैं और ऊर्जा एवं वित्त का दुरुपयोग हथियारों के रूप में किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस वास्तविकता को स्वीकार करने के बावजूद, सरकार ने संयुक्त राज्य अमेरिका को ऊर्जा और वित्तीय प्रणालियों का इस तरह से दुरुपयोग करने की अनुमति दी है जिससे भारत प्रभावित हो रहा है।

रिजिजू ने लोस अध्यक्ष के चैंबर का फिर जारी किया वीडियो

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने गुरुवार को फिर से दोहराया कि कांग्रेस सांसदों ने स्पीकर ओम बिरला को उनके चैंबर में गाली दी थी। उन्होंने कहा कि भाजपा बहस और चर्चा में विश्वास करती है और किसी भी प्रकार की शारीरिक या मौखिक धमकी का समर्थन नहीं करती है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में, रिजिजू ने एक कांग्रेस सांसद द्वारा रिकॉर्ड किया गया एक अवैध वीडियो साझा किया। उन्होंने आरोप लगाया कि लगभग 20-25 कांग्रेस सांसद स्पीकर के चैंबर में घुस गए, उन्हें गाली दी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धमकी दी। रिजिजू ने लिखा कि यह एक कांग्रेस सांसद द्वारा बनाया गया अवैध वीडियो क्लिप है, जिसमें 20-25 कांग्रेस सांसद स्पीकर के चैंबर में घुस गए, उन्हें गाली दी और माननीय प्रधानमंत्री को धमकी दी। हमारी पार्टी बहस और चर्चा में विश्वास करती है और सांसदों को शारीरिक रूप से धमकी देने के लिए कभी प्रोत्साहित नहीं करती है। बुधवार को किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सदस्यों ने स्पीकर

के कक्ष में घुसकर उन्हें अपशब्द कहे।पत्रकारों से बात करते हुए रिजिजू ने कहा कि स्पीकर इस घटना से गहराई से आहत हुए हैं और उन्होंने व्यक्तिगत रूप से उनसे बात की है। उन्होंने सदन में बोलने की अनुमति को लेकर हुए विवाद का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि स्पीकर द्वारा एक आदेश जारी किए जाने के बाद, कथित तौर पर उसका पालन नहीं किया गया। उन्होंने दावा किया कि राहुल गांधी ने कहा था कि उन्हें बोलने के लिए किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं है और वे अपनी इच्छानुसार बोलेंगे।

एक्स पोस्ट फैक्टो मंजूरी केस में जयराम रमेश ने वापस ली याचिका

» सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद लिया फैसला

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता जयराम रमेश की उस याचिका पर सख्त टिप्पणी की है, जिसमें एक्स पोस्ट फैक्टो (पूर्व प्रभाव से) पर्यावरणीय मंजूरी देने की प्रक्रि या को कानून के खिलाफ बताया गया था। सुनवाई के दौरान अदालत ने साफ कहा कि किसी पहले से दिए गए निर्णय की समीक्षा रिट याचिका के जरिए नहीं मांगी जा सकती।

अदालत ने पूछा आपने इस मुद्दे पर पुनर्विचार याचिका क्यों नहीं दाखिल की? मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत ने सुनवाई के दौरान कहा कि यह मामला दरअसल कोर्ट के ही पुराने फैसले से जुड़ा है। ऐसे में रिट याचिका के माध्यम से सीधे चुनौती देना उचित प्रक्रिया नहीं है। सीजेआई ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कोई पक्ष इस तरह से कोर्ट के फैसले की समीक्षा चाहता है, तो उसे भारी जुर्माने के लिए तैयार रहना चाहिए. उन्होंने यह भी टिप्पणी की कि इस तरह की याचिकाएं कई बार सिर्फ मीडिया में चर्चा पाने के लिए दायर की जाती हैं।

घूसखोर पंडत के मेकर्स को सुप्रीम कोर्ट से कड़ी फटकार

» शीर्ष अदालत बोली- किसी भी वर्ग को अपमानित करना गलत, अगली सुनवाई 19 को

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। फिल्म घूसखोर पंडत के निर्माता को सुप्रीम कोर्ट से कड़ी फटकार मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा किसी भी वर्ग को अपमानित करना गलत है। समाज में पहले ही इतनी दरार है। आप इसे बढ़वा मत दीजिए।

कोर्ट ने नोटिस जारी किया और कहा आपने नाम बदलने की बात कही है, हमें बताइए कि नाम क्या रखने जा रहे हैं? यह भी बताइए कि आपकी फिल्म में किसी वर्ग के बारे में कोई आपत्तिजनक बात है या नहीं? इस मामले की अगली सुनवाई 19 फरवरी को होगी। बता दें इस फिल्म व इसके टाइटल को कई सियासी दलों ने भी आपत्ति की थी। वहीं ब्राहमणों ने भी इसका खुला विरोध किया था।

तंबाकू कारोबारी का बेटा शिवम मिश्रा गिरफ्तार

लैंबॉर्गिनी हादसे के मामले में पुलिस की कार्रवाई

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

कानपुर। कनपुर शहर के पॉश ग्वालटोली इलाके में हुए भीषण लैंबॉर्गिनी हादसे के मामले में कानपुर पुलिस ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने मशहूर तंबाकू उद्योगपति के.के. मिश्रा के बेटे शिवम मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया है।

8 फरवरी को हुई इस घटना में छह लोग घायल हुए थे और कई वाहनों को नुकसान पहुँचा था। यह दुर्घटना 8 फरवरी को दोपहर करीब 3 बजे वीआईपी रोड पर हुई। करीब 10 करोड़ रुपये की कीमत वाली लग्जरी इटैलियन स्पोर्ट्स कार लैंबॉर्गिनी रेवुएल्टो ने अनियंत्रित होकर पैदल यात्रियों और अन्य गाड़ियों को जोरदार टक्कर मारी थी। टक्कर के बाद कार डिवाइडर पर चढ़कर रुक गई। इस मामले में 18 वर्षीय ई-रिक्शा चालक मोहम्मद तौफीक की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई थी।

कंटेनर से टकराई कार, दो महिलाओं की मौत

» दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे पर हुआ हादसा

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर इलाके में गुरुवार सुबह दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे (राष्ट्रीय राजमार्ग-9) पर दिल्ली नगर निगम टोल प्लाजा के पास एक कार की कंटेनर ट्रक से टक्कर होने से दो महिलाओं की मौत हो गई और दो बच्चों सहित तीन अन्य घायल हो गए।

विनोद नगर डिपो के सामने हुई यह टक्कर इतनी तेज थी कि कार ट्रक में जा घुसी. एक महिला कार के बाहर सड़क पर पड़ी थी,

जबकि दूसरी सीट पर बुरी तरह फंसी हुई थी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक यह हादसा विनोद नगर डिपो के सामने टोल बूथ के पास सुबह 6:43 बजे हुई। गाजियाबाद की तरफ से आ रही एक किआ सेल्टोस कार टोल प्लाजा के पास एक कंटेनर ट्रक से टकरा गई। एक अधिकारी ने बताया कि मौके पर पहुंचने पर टीम ने कार में सवार दो महिलाओं को अचेत पाया। उनकी पहचान दीपांजलि (38) और नीलम गर्ग (55) के रूप में हुई। एक महिला वाहन के बाहर पड़ी मिली, जबकि दूसरी आगे की बाईं तरफ की यात्री सीट पर फंसी हुई थी। दोनों को घटनास्थल पर ही मृत घोषित कर दिया गया। कार की हालत दिखा रही है कि टक्कर कितनी भीषण थी। पुलिस ने मौके पर क्रेन मंगवाकर गाड़ी को बाहर निकलवाया। घायलों का अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है।

महाराष्ट्र कार्यालय:- 2 जी, कृष्णा कुटीर सागरिका CHS जुहू तारा रोड जुहू- मुंबई- 400049। विधि सलाहकार: मोहम्मद हैदर
*इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी।
RNI-UPHIN/2015/62233, दूरभाष: 0522- 4078371 | Email: daily4pm@gmail.com | website: www.4pm.co.in |
समस्त विवाद लखनऊ न्यायालय के अधीन ही होंगे।

स्वामी 4 पीएम न्यूज नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड के लिए
मुद्रक एवं प्रकाशक संजय शर्मा
द्वारा आस्था प्रिंटर्स, 5/600, विकास खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010 (यूपी) से मुद्रित
पता 5/600, विकास खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010 (यूपी) से प्रकाशित। संपादक- संजय शर्मा